DCWC Newsclip

Vol XXI **Issue 01/01** **January 2015**

SPECIAL ISSUE
(BETI BACHAO BETI PADHAO)

2015
Documentation Centre on Women and Children (DCWC)
National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD)
5, Siri Institutional Area, Hauz Khas
New Delhi - 110016

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जागरूकता रैली निकाली

नारनौल, 8 जनवरी (निस)

आंगनबाड़ी विभाग द्वारा चलाए जा रहे 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' अभियान के तहत आज गांव गोमला व गोमली में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसमे मुख्यातिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपर वाइजर केला देवी ने शिरकत की। जबकि रैली का नेतृत्व आंगनबाड़ी वर्कर सुनीता यादव ने किया।

मुख्यातिथि ने आंगनबाड़ी वर्कर्स, सहायिकाओं व गांव की महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या रोकने एवं बेटियों की रक्षा करने तथा पढ़ाने के बारे जागरूक किया। मुख्यातिथि ने ग्रामीणों को कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह व दहेज प्रथा जैसी समाज में फैली बुराईयों को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया। इस

नारनौल में शनिवार को गांव गोमला में बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत जागरूक रैली निकालती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। -निस

अवसर पर शान्ति देवी, संतोष देवी, सुनीता यादव, सविता, नीलम व सुमन सहित अनेक प्रवीना, स्नेहलता, किरोशिता, शकुन्तला, अन्नू, कविता, पुष्पा, महिलाएं उपस्थित थी।

Dainik Tribune (H) , January 9, 2015, P. 6

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ' के तहत कार्यक्रम आयोजित

नारनौल/पलवल, 9 जनवरी (अस/एस/निस)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा व सर्व धर्म एवं जन परोपकारी संस्था नई दिल्ली की नारनौल शाखा द्वारा आयोजित 'बेटी-बचाओ, बेटी तहत आज गांव हुडिना रामपुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता मुकेश कुमारी ने शिरकत की।

मुकेश कुमारी ने कहा कि बेटियों में ही हमारा भविष्य है।पंकज कुमार ने कहा कि लड़कियों को बचाना ही समाज में अपने अस्तित्व को बचाना है।

सूचना,जनसम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा के महानिदेशक अभिलक्ष लिखी के निर्देशानुसार जिला पलवल में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम शुरू किया गया है। गत एक जनवरी से शुरू किया गया यह कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी तक चलेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष गिर्राज सिंह डागर तथा सत्यभान शर्मा ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं हरियाणा सरकार की सराहना की।

समाजसेवी संस्था लोकसंस्कृति संरक्षण प्रकोष्ठ के सौजन्य से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के तहत नारनौल में जागरूकता व हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अपने इस हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रकोष्ठ के सदस्यों ने घर-घर जाकर लोगों को जिला महेंद्रगढ़ में स्त्री-पुरुष अनुपात को आने वाले समय में चिन्ता का विषय बताते हुए कन्या भ्रूण-हत्या जैसे जघन्य अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे आने की अपील की।

Dainik Tribune (H) , January 10, 2015, P. 7

मोदी 'बेटी बचाओ' को अभियान बनाएंगे

पहल

नई दिल्ली |सुहेल हामिद

स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे और मेक इन इंडिया अभियान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को 'बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ' अभियान की शुरुआत करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि हरियाणा के पानीपत से शुरू होने वाले इस अभियान में सभी प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों के चुनिंदा शहरों को शामिल किया जाएगा। 'बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ' अभियान की शुरुआत से पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पानीपत में इस विषय पर दो दिन की कार्यशाला भी आयोजित की है। इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।

बता दें कि मोदी लड़कियों के साथ भेदभाव खत्म करने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने का आह्वान कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर उन्होंने बेटियों के साथ भेदभाव खत्म करने और समानता का माहौल बनाने की अपील करते हुए इस बारे में लोगों से सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के आधार पर सरकार ने 'बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ' अभियान को अंतिम रूप दिया है।

बालिका संरक्षण

- 22 जनवरी को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री करेंगे अभिया की शुरुआत
- सभी प्रदेश और केंद्र शासित राज्य होंगे इसमें शामिल

मुख्य बिंदु

- सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगाए जाएंगे। इनमें गांव में हर माह का लिंग अनुपात दर्ज होगा
- ग्राम पंचायत लड़की के जन्म पर परिवार को तोहफा भेजेगी। पंचायत साल में कम से कम एक दर्जन लड़कियों का जन्मदिन मनाएगी
- सभी ग्राम पंचायतों में लोगों को 'बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ' की शपथ दिलाई जाएगी
- गांव में लिंग अनुपात सुधारेगा तो ग्राम पंचायत को सम्मानित करेंगे
- बाल विवाह के लिए ग्राम प्रधान को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी

Hindustan (H), January 10, 2015, P. 14

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की निगरानी करेगा राष्ट्रीय कार्यबल

नई दिल्ली, (वार्ता): सरकार के महत्वाकांक्षी 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के निर्देशन और निगरानी के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। सूत्रों ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान मूल रूप से केंद्र सरकार का है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। हालांकि इस संबंध में निर्देशन और निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक कार्यदल का गठन होगा और बजट आवंटन भी केंद्र सरकार करेगी। इस कार्यदल के अध्यक्ष केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव होंगे जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव विकास संसाधन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विकलांगता संबंधी विभाग, लिंग अनुपात विशेषज्ञ और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। कार्यदल विभिन्न राज्यों द्वारा इस संबंध में बनाई योजनाओं की समीक्षा करेगा और उचित सुझाव और सहयोग देगा।

कर्मचारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की विषय वस्तु तैयार करने की जिम्मेदारी भी इसी कार्यबल की होगी। यह कार्यबल सयुंक्त संचार कार्रवाई के लिए एक उप समिति का भी गठन करेगा। कार्यबल की बैठक प्रति तिमाही आयोजित की जाएगी। राज्य में भी महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया जाएगा और जिला स्तर पर अभियान का निर्देशन और निगरानी करेगा। यह अभियान एक सौ जिलों में लागू किया जा रहा है। इनमें 95 ऐसे जिले शामिल हैं जिनमें बालक- बालिका अनुपात बढ़ रहा है और राष्ट्रीय औसत से कम है। बाकी पांच जिले ऐसे हैं जिनमें बालक-बालिका अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और यह अनुपात घट रहा है। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी को शुरू करेंगे।

Punjab Kesari (H), January 13, 2015, P. 3

Dainik Tribune (H) , January 14, 2015, P. 1

आशा वर्कर लेंगी 'बेटियों' को बचाने की शपथ

चंडीगढ़, 14 जनवरी (ट्रिब्यू)

सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत आशा वर्कर एवं एएनएमएस 'बेटियों' की रक्षा करने की शपथ लेंगी। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने यह मुहिम छेड़ी है।16 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय के अलावा सभी जिलों में संकल्प समारोह आयोजित किए जाएंगे।

यह मुहिम 22 जनवरी को पानीपत से शुरू होने वाले 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लक्षित समूह को संवेदनशील बनाने में एएनएमएस और आशा वर्कर्स, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिये सरकार खापों की मदद भी ले सकती है।

Dainik Tribune (H) , January 15, 2015, P. 3

PM to launch 'Beti Bachao' with a bang on January 22

Scheme To Focus On Low Child Sex Ratio

Himanshi.Dhawan
@timesgroup.com

New Delhi: After Swachh Bharat and Make In India, the Modi government's big bang flagship scheme will be 'Beti Bachao, Beti Padhao' (BBBP), which will help address the country's low child sex ratio. The scheme will be launched by PM Narendra Modi on January 22 and will focus on a multi-sectoral approach to tackling the problem of the vanishing girl child.

A toilet in every girls' school in 100 vulnerable districts, an innovation fund at state-level to encourage best practices in improving child sex ratio (CSR) and gender inequities, district-level awards to schools strengthening girl child education are some of the targets that the scheme hopes to accomplish by 2017.

The Rs 100-crore scheme is expected to be monitored by the Maneka Gandhi-headed ministry of women and child development (WCD) in coordination with the ministries of health and HRD. Audits are expected to be done by civil society and the CAG to ensure that targets are met.

The launch is expected to be a high-wattage affair with Union ministers, chief ministers of West Bengal, Rajasthan, Gujarat and Haryana and senior officials attending it.

The objectives of the scheme is to prevent gender-biased sex selection by stringent enforcement of laws, especially by strengthening the implementation of Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (PC&PNDT Act) with strict punishments for violations.

BBBP will also ensure access and availability of essential requirements related to nutrition, healthcare, education and protection and elimination of discrimination against a girl child which can lead to low self-esteem, lifelong deprivation and exclusion from the mainstream.

Initiatives will be taken to encourage girls to express their views and to be heard, to help them participate actively effectively and equally at all levels of social, economic, and political leadership. Long-term interventions for gender equality would focus on creating enabling environment. The objectives will be achieved through convergence and coordination with concerned ministries, departments and district administration.

The decline in the CSR, defined as number of girls per 1,000 boys between 0-6 years, has been unabated since 1961. The decline from 945 in 1991 to 927 in 2001 and further to 918 in 2011 is alarming.

TARGETS FOR GIRL CHILD CAMPAIGN

1. **Improve sex ratio at birth** in 100 gender critical districts by 10 points in a year (all-India CSR is 918 females to 1,000 males according to the 2011 census)
2. **Reduce gender differentials** in under-five child mortality rate from 59:51 for girls vs boys in 2011 to 55 for girls in 2017
3. **Improve nutrition status of girls** under 5 by reducing number of underweight and anaemic girls (Currently, 7 of 10 children are anaemic and 42.5% underweight)
4. **Ensure universalization of ICDS, girls' attendance** and **equal care monitored**, using joint ICDS NRHM Mother Child Protection Cards
5. **Increase girl's enrolment** in secondary education from 76% in 2013-14 to 79% by 2017
6. **Provide toilet for girls in every school** in 100 districts by 2017
7. **Promote a protective environment for girl children** through implementation of Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act 2012
8. **Train elected representatives/ grassroot functionaries** as Community Champions to mobilize communities to improve CSR & promote education for girls

Budget allocated: ₹100cr.
Scheme cost is however about ₹200cr

HIGH-VOLTAGE LAUNCH BY PM MODI ON JAN 22

The Times of India, January 15, 2015, P. 13

'स्वास्थ्य कर्मियों पर बेटी बचाने का जिम्मा'

जींद,17 जनवरी। हप्र

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ की जिम्मेदारी अब महिला स्वास्थय कर्मियों के कंधो पर आ रही है। बहु उद्देश्यीय स्वास्थय कर्मियों ,एएनएम और आशा कर्मियों को अब सरकारी अस्पतालों मे इस योजना को लेकर घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलवाई जा रही है। विभाग को सरकार के यह आदेश भी मिल चुके हैं कि सभी एमपीएचडब्ल्यू, एएनएम,आशा वर्कर 22 फरवरी को पानीपत में प्रस्तावित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करें। प्रदेश के स्वास्थय विभाग ने भी इस योजना को लोगों के घर-द्वार पहुंचाने की तैयारी कर ली है। किशोर हेल्थ कांउसलर रितु खोखर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों ने संकल्प लिया है कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को पढ़ाने के लिए लोगो को जागरुक करेंगे।

अधिकारी भी करें सहयोग

स्वास्थ सुपरवाइजर संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि उच्च अधिकारियों को भी इस कार्य में पूरा सहयोग करना चाहिये।

Dainik Tribune (H) , January 18, 2015, P. 10

SAVING, EDUCATING GIRL CHILD

Slew of measures unveiled in Haryana

Prelude to national programme to be launched by PM on January 22

Gaurav Vivek Bhatnagar

CHANDIGARH: From focussing on 12 districts of Haryana with the most skewed sex ratio, to urging women in the households to boycott those who favour female foeticide, to rewarding schools which enrol the highest number of girl students, Union Ministers and Haryana Ministers on Saturday announced a slew of measures for saving and educating the girl child in the State.

Awareness yatras

The Ministers flagged off Awareness Yatras in different districts as a prelude to Prime Minister Narendra Modi launching the Beti Bachao Beti Padhao national programme from Panipat on January 22.

Union Minister for Rural Development Birender Singh urged women to boycott those who pressured them or others to resort to female foeticide. Mr. Singh said the Beti Bachao Beti Padhao programme seeks to eradicate this practice.

State Health Minister Anil Vij urged social and religious institutions and khap panchayats to support the national programme and take a pledge that they would not let female foeticide take place in their areas. The school managements, which will ensure maximum enrolment of girls, would be awarded, he declared.

Mr. Vij said besides saving the girl child, her education was necessary.

He said the programme would be implemented in 100 districts of the country, out of which 12 districts of Haryana with the lowest sex ratio have been selected. These are Mahendergarh, Jhajjar, Rewari, Sonepat, Ambala, Kurukshetra, Rohtak, Karnal, Yamuna Nagar, Kaithal, Bhiwani and Panipat.

In Sonepat, Haryana Women and Child Development Minister Kavita Jain said the scheme would "spread awareness among people regarding security of girls, female foeticide, declining sex ratio, education and empowerment of women."

The yatras would travel to different parts over three days and sensitise people about these burning issues.

Haryana CM M.L. Khattar launches the Beti Bachao, Beti Padhao campaign in Chandigarh on Saturday. – PHOTO: PTI

The Hindu, January 18, 2015, P. 7

(*Campaign-Beti Bachao Beti Padhao*)

PM to launch Beti Bachao campaign on January 22

Staff Reporter

GURGAON: In order to improve the skewed sex ratio in Gurgaon, a "Beti Bachao-Beti Padhao" campaign awareness yatra was flagged off by Haryana PWD (B&R) and Public Health Minister Rao Narbir Singh at Swatantarta Senani Zila Parishad Bhawan here on Sunday. He also released a calendar of "Beti Bachao-Beti Padhao" campaign.

Mr. Singh said that Prime Minister Narendra Modi would launch the national programme of "Beti Bachao-Beti Padhao" campaign on January 22 at Panipat.

He said that the Prime Minister was concerned about the imbalance in sex ratio and also about the low literacy rate among females; therefore, he thought of launching the campaign to generate awareness among the public. He made an appeal to the people to curb female foeticide and provide education to their daughters.

No programme or policy can become successful without the participation of the masses; the government alone could not achieve the target; and a mass movement was necessary for bringing a social awakening.

"Beti Bachao-Beti Padhao" campaign awareness yatra was flagged off by PWD (B&R) and Public Health Minister Rao Narbir Singh

The Hindu, January 19, 2015, P. 4

बेटियों को बचाने, पढ़ाने में करें सहयोग : गुर्जर

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जनजागृति यात्रा को दी झण्डी

फरीदाबाद, 18 जनवरी (हप्र)

फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित हूडा कन्वेंशन सेन्टर से रविवार को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जनजागृति यात्रा को झण्डी देते हुए केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। -शिव

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जनजागृति यात्रा को फरीदाबाद के सैक्टर-12 स्थित कन्वेंशन सैन्टर से झण्डी दिखाकर को रवाना किया। इस अवसर पर गुर्जर ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारम्भ किए जा रहे बेटियों को बचाने तथा पढ़ाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम को एक जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में देश के सभी नागरिक अपना सक्रिय सहयोग दें। इस मौके पर केन्द्रीय राज्यमंत्री ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित एक कैलेंडर भी जारी किया। केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर ने कहा कि सरकार केवल जनजागृति उत्पन्न करने का कार्य कर सकती है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसामान्य की भागीदारी अति आवश्यक है। बेटियों को बचाने तथा पढ़ाने के प्रधानमंत्री के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को धरातलीय रूप देने में देश के नागरिकों को सेवा-समर्पण भाव से कार्य करना होगा।

हूडा कन्वेंशन सैन्टर से झण्डी देकर रवाना की गई 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जनजागृति यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई गांवों में भी पहुंची। समारोह में विधायक विपुल गोयल, विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक टेकचन्द शर्मा, भाजपा नेता राजेश नागर, भाजपा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय गौड़, उमेश भाटी, नयनपाल रावत, नगराधीश गौरव अंतिल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेश पंकज, हूडा के कार्यकारी अधिकारी सतपाल सिंह मौजूद थे।

Dainik Tribune (H) , January 19, 2015, P. 7

फरीदाबाद में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जागृति यात्रा शुरू

फरीदाबाद,19 जनवरी (जनसत्ता)। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने रविवार को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जनजागृति यात्रा को झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए जा रहे बेटियों को बचाने और पढ़ाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम को एक जनआंदोलन का रूप देने में अपना सहयोग दें।

गुर्जर ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ से संबंधित एक कैलेंडर भी जारी किया। महिलाओं के उत्थान और कल्याण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को पानीपत में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम पहले देश के सौ जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें हरियाणा के भी 12 जिले शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम के प्रति समाज में जनसंवेदनाएं, जनजागृतियां और जनचेतनाएं उत्पन्न करने की दिशा में 1 जनवरी से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में 17 जनवरी से जनजागृति यात्राएं निकाली जा रही हैं।

जनजागृति यात्राओं के इस क्रम में फरीदाबाद के सैक्टर-12 स्थित हुडा कन्वेंशन सैंटर में आयोजित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जनजागृति यात्रा समारोह में गुर्जर ने कहा कि सरकार केवल जनजागृति उत्पन्न करने का कार्य कर सकती है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसामान्य की भागीदारी अति आवश्यक है। बेटियां बेटों की अपेक्षा अधिक सहनशील होती हैं। सभी क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की उपलब्धियां बेटों से कही अधिक हैं। सरकार के अतिरिक्त समाज में बेटियों को बचाने, पढ़ाने, सिखाने और रोजगार दिलाने का कार्य करना है। समाज को बेटियों के सभी आर्थिक और सामाजिक अधिकार उन्हें देने होंगे ताकि सशक्त राष्ट्र के निर्माण में बेटियों की भी अहम भूमिका रहे।

उपायुक्त अमित कुमार अग्रवाल ने असंतुलित लिंगानुपात के लिए कन्या भ्रूण हत्या को कारक बताते हुए कहा कि समाज को अब अत्यंत सचेत एवं जागृत होने की नितांत आवश्यकता है। सन फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने कहा कि कन्याओं के आर्थिक उत्थान के लिए उनकी संस्था सदैव सक्रिय सहयोग करेगी। इस मौके पर मोदी के संदेश से संबंधित वीडियो भी दिखाई गई और सूचना,जनसंपर्क और सांस्कृतिक कार्य विभाग की भजन मंडली द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के प्रति सचेत करने के लिए भजन प्रस्तुत किया गया। समारोह का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त आदित्य दहिया के समन्वयन में किया गया। हुडा कन्वेंशन सैंटर से झंडी देकर रवाना की गई बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जनजागृति यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई गांवों में भी पहुंची। समारोह में विधायक विपुल गोयल, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक टेकचंद शर्मा, भाजपा नेता राजेश नागर, भाजपा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय गौड़ भी मौजूद थे। इसके अलावा नगराधीश गौरव अंतिल, जिला विकास और पंचायत अधिकारी नरेश पंकज, हुडा के कार्यकारी अधिकारी सतपाल सिंह, सन फाउंडेशन की निदेशक चित्रा साधु और मुख्य ऑप्रिशनं अधिकारी ईशा भंडारी भी मौजूद थी।

Jansatta (H), January 20, 2015, P. 4

हरियाणा

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर राष्ट्रीय कार्यशाला का दूसरा दिन

महिला दिवस पर देशभर से 660 महिलाएं होंगी सम्मानित

एनसीआरईटी की किताबों में लिखे जाएं महिला अधिकार

पानीपत/सोनीपत, 21 जनवरी (हप)

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर पहली बार जिला महिला सम्मान पुरस्कार से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली देश भर की 660 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए फरवरी माह के अंत तक केंद्रीय मंत्रालय को नामांकन जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

मेनका गांधी बुधवार को पानीपत में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित नवदिशा कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात के प्रति लोगों को जागरूक कर तथा कार्यशाला में हुए मंथन का निचोड़ निकाल कर और उसे अमलीजामा पहनाते हुए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए महिलाओं से विचार-विमर्श के लिए एक मंच होना जरूरी है। हरियाणा, राजस्थान व गुजरात जैसे राज्यों में आंगनवाड़ी एवं सामुदायिक केंद्रों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है, परंतु उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह स्थिति काफी चिंताजनक है। इस पर हमें जोर देना चाहिए। उन्होंने कहाकि जिला मजिस्ट्रेट मनरेगा के तहत भी ऐसे भवनों का निर्माण करवा सकते हैं।

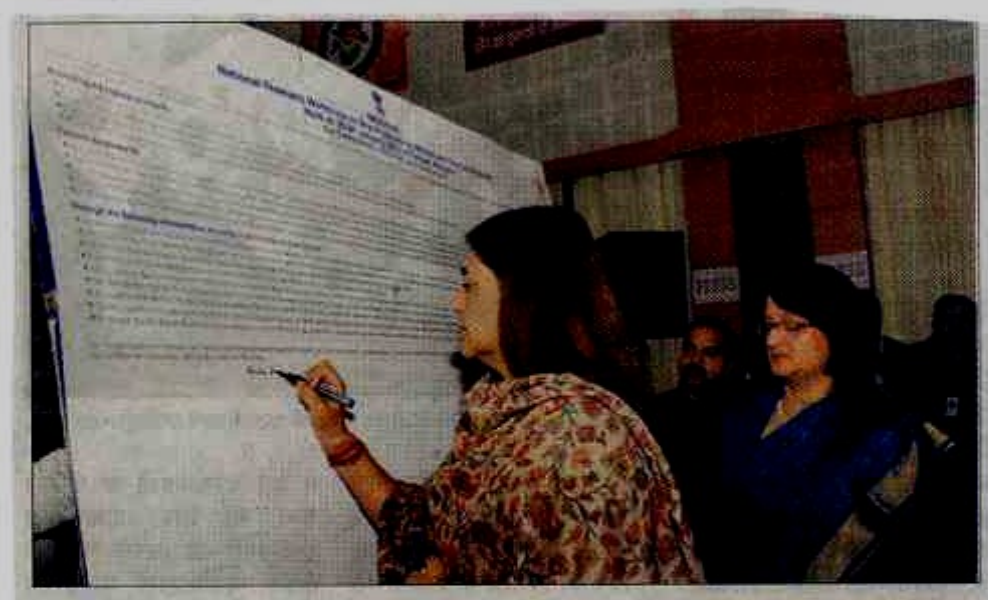

पानीपत में बुधवार को राष्ट्रीय बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यशाला के दौरान केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ शपथपत्र पर साइन करते हुए। -रवि कुमार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गर्भपात प्रक्रिया की एक फिल्म भी दिखाई जानी चाहिए, जैसा की गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन ने अपने संबोधन में स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सेम्युअल की आत्मकथा का जिक्र किया था, जिन्होंने फिल्म देखने के बाद अपना अस्पताल बंद करने का निर्णय लिया था।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी एवं हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने लिंगानुपात पर शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित स्लोगन, निबंध लेखन एवं पेंटिंग प्रतियोगिता के 22 स्कूली छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया। सबसे पहले कस्तूरबा गांधी विद्यालय नूंह मेवात की छठी कक्षा की छात्रा वसीमा को सम्मानित किया गया। इनको केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत का ब्रांड अंबेसडर भी बनाया है। समारोह में सीएम मनोहर लाल, विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर, सांसद रमेश कौशिक के अलावा भाजपा के विधायक, मुख्य सचिव डीएस ढेसी व अन्य मौजूद थे।

Contd...

केंद्र की सबला योजना में भी संशोधन की तैयारी

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों के अंतिम पृष्ठ पर महिलाओं के क्या हक हैं? के संबंध में जानकारी का पेज छपा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार की सबला योजना में संशोधन के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बात कर रहा है। इसके लिए पहले सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाकर सहमति देनी होगी। गांधी का यह भी सुझाव था कि स्कूल छुट्टी के पश्चात सप्ताह में दो दिन 14 साल से अधिक उम्र के लड़के व लड़कियों को अतिरिक्त समय देकर उनके अधिकारों के बारे जानकारी दी जानी चाहिए तथा इसके लिए परीक्षाएं भी आयोजित की जानी चाहिए।

बेटी बचाने का संकल्प और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पर रहा जोर

पुरुषोत्तम शर्मा / हप
पानीपत/सोनीपत, 21 जनवरी

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान वर्तमान चुनौतियों तथा भविष्य की योजनाओं पर मंथन किया गया। इनमे कुछ मुद्दों पर सर्वसम्मति बनी, तो कई मुद्दों पर सुधार की गुंजाइश महसूस की गई। कार्यशाला में महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, नवजात शिशुओं के समक्ष पोषाहार, स्वास्थ्य, मानव तस्करी, बाल विकास एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभिन्न राज्यों के मंत्री व अन्य प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों ने पैनल चर्चा में हिस्सा लिया।

कार्यशाला में इस बात पर बल दिया गया कि ऐसी योजनाएं बनें, जो देशव्यापी हों और हर इलाके में कारगर ढंग से कामकाज को बेहतर कर सकें। इसके लिए गहन मंथन के बाद जो तथ्य उभरकर सामने आया है, उसमें बेटी बचाने का संकल्प और लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता को पहला पायदान माना गया। इसके लिए सुरक्षा और महिलाओं व बच्चियों के लिए बेहतर योजनाओं की भी दरकार महसूस की गई। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने मानव तस्करी को लेकर नयी चुनौतियों से रुबरु कराया। उन्होंने कहा कि कठोर कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तथा संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी इच्छा शक्ति के अभाव में इसे मौन स्वीकृति देकर अंकुश नहीं लगाया जा रहा।

महिला दिवस पर होगी नयी योजना की घोषणा

महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने बताया कि मानव तस्करी के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए इस विषय को पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार वर्तमान में संचालित लाडली योजना का संशोधन करने जा रही है जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने संबोधन में कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर लिंगानुपात में प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं जिसके तहत 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये व 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

कार्यशाला के दौरान एक बच्ची को सम्मानित करते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी। हप

Dainik Tribune (H) , January 22, 2015, P. 3

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ रथ को किया रवाना

नारनौल, 19 जनवरी (निस)

जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज दौंगडा अहीर से एसडीएम कनीना सतबीर सिंह ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व अटेली सीडीपीओ कार्यालय से डीआईपीआरओ उषा रानी ने आंगनवाड़ी वर्करों को बेटी बचाने की शपथ दिलवाई। इस मौके पर उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए एसडीएम सतबीर सिंह ने कहा कि यह अभियान प्रदेश के 12 जिलों में चलाया जा रहा है, जहां लिंगानुपात में भारी अंतर है। इसी अभियान के तहत 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में राष्ट्रीय कार्यक्रम बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। इस अभियान की शुरुआत आज अटेली खंड के गांव गणियार से की गई। इस अभियान के अंतर्गत आज गांव गनियार, बिहाली, कांटी, खेड़ी, नाउदी, खोड़, ताजपुर,बाछौद, गुवानी, कुंजपुरा, भूषण कलां, पटीकरा, कोजिंदा, मंढाणा, कांवी, कुलताजपुर, कोरियावास, भांखरी, दौचाना, बलाहा-कलां में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजन किया गया।

Dainik Tribune (H) , January 20, 2015, P. 6

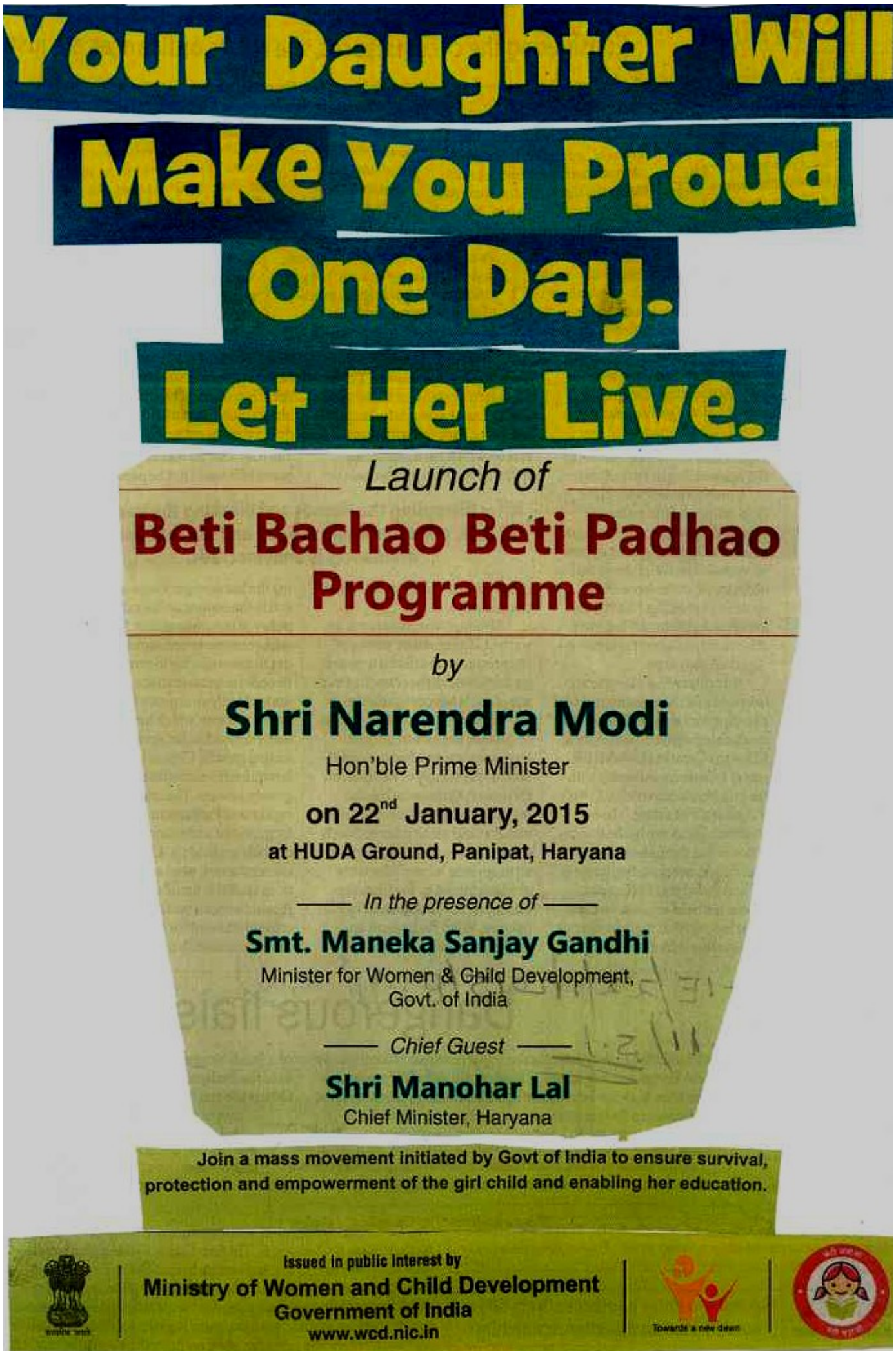

The Indian Express, January 22, 2015, P. 11

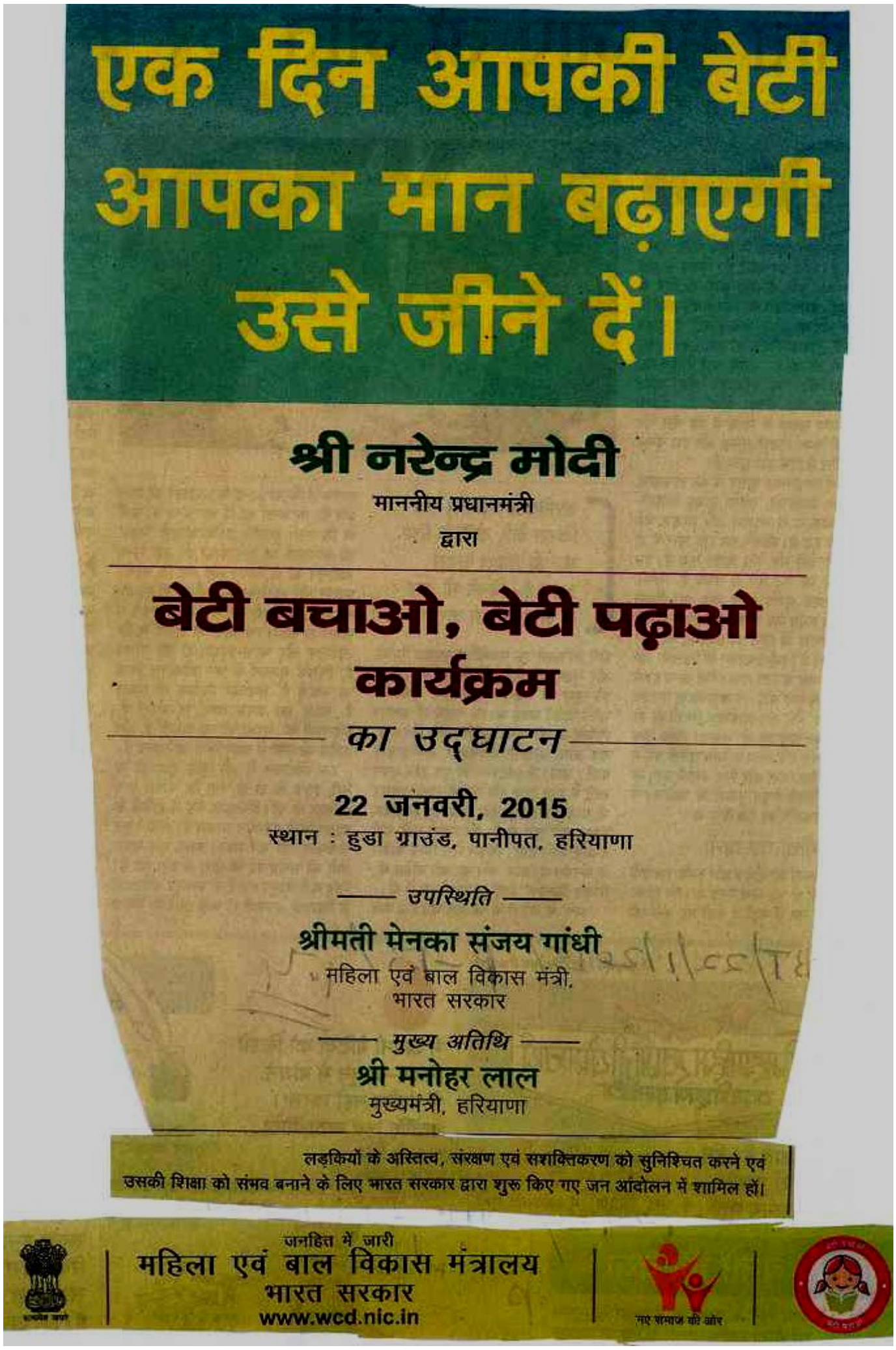

Nav Bharat Times (H), January 22, 2015, P. 13

हरियाणा

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री खट्टर की घोषणा

अब पहली बेटी के जन्म पर ही 21 हजार का 'आशीर्वाद'

पानीपत में बृहस्पतिवार को आयोजित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के दौरान डाक टिकट जारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ सीएम मनोहर लाल, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, बीरेंद्र सिंह, कृष्णपाल गुर्जर व अन्य मौजूद रहे। हप

रैली में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं

- लड़कियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी।
- सभी स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य पोषण मिशन बनाया जाएगा।
- मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा का एजेंडा
- विधायक व अधिकारी आदर्श ग्राम योजना शुरू होगी

"महिला साक्षरता प्रतिशत का प्रतिशत चिंताजनक है। वर्तमान में प्रदेश की महिला साक्षरता दर 65.4 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 80 प्रतिशत है, हमें दोनों को 100 प्रतिशत करना होगा। इसके लिए सरकार लड़कियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। हरियाणा ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।"

-मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री

पानीपत/सोनीपत, 22 जनवरी (हप्र)

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहले से संचालित लाडली सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब लाडली योजना के तहत बीपीएल व अनुसूचित जाति के परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके तहत हरियाणा कन्या कोष तथा स्वस्थ हरियाणा के लिए हरियाणा स्वच्छता कोष स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वीरवार को शुरू किए गए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार रख रहे थे। खट्टर ने कहा कि पहले लाडली स्कीम के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता दी जाती थी। अब पहली बेटी के जन्म पर ही 21,000 रुपये जमा करवाये जाएंगे और 18 वर्ष के बाद यह राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने महिला साक्षरता प्रतिशत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश की महिला साक्षरता दर 65.4 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 80 प्रतिशत है, हमें दोनों को 100 प्रतिशत करना होगा। इसके लिए सरकार लड़कियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कोई भी बच्चा जमीन पर बैठ कर न पढ़े, इसके लिए सरकार ने 2016 तक सभी स्कूलों में बच्चों के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। वहीं हर स्कूल में बेटियों के लिए टॉयलेट बनाए जाएंगे।

मेक इन हरियाणा लागू करेंगे

मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि प्रदेश में बच्चों और माताओं में कुपोषण की दर भी चिंताजनक है। इस कड़ी में भी राज्य स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर राज्य पोषण मिशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को यदि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप प्रदेश घोषित किया जाए, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि

Contd...

मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही मेक इन हरियाणा हमारा एजेंडा है। खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हरियाणा ने शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।

समारोह से पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका संजय गांधी, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के अलावा केबिनेट मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में लिंगानुपात सुधार के कार्यक्रमों को लेकर लगाए गए चार्ट की जानकारी ली।

समारोह में मुख्यमंत्री ने एक बच्ची को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक महीपाल ढांडा, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव सुमिता मिश्रा, डॉ. राकेश गुप्ता, मीडिया सलाहकार अमित आर्य व ओएसडी (मीडिया) राजकुमार भारद्वाज, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता, सूचना जन संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के महानिदेशक डा. अभिलक्ष लिखी भी उपस्थित थे।

पानीपत में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत के दौरान रूक-रूक कर बूंदाबांदी होती रही। समारोह में पहुंची महिलाओं ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। महिलाओं ने उन पैंफलेट को अपने सिर पर रख लिया जिनके ऊपर बेटियों के संबंध में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई है। -हप

सड़क मार्ग से गए मोदी

पानीपत (हप्र): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच जिले की सीमा से गुजरा। चप्पे-चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक बी सतीश बालन मुस्तैदी से निगरानी कर रहे थे। पीएम का कार्यक्रम हवाई मार्ग से पानीपत पहुंचने था, पर मौसम में आई खराबी के कारण अचानक उनका कार्यक्रम सड़क मार्ग से पानीपत जाने का बना दिया गया। एक बजकर 35 मिनट पर प्रधानमंत्री का काफिला कुंडली बार्डर से प्रदेश की सीमा में प्रविष्ट हुआ। काफिले में सुरक्षा के मद्देनजर एक ही नंबर की काल रंग की 10 गाड़ियों को शामिल किया गया था।

रैली की झलकियां

बेटियों के लिए मिलकर लें संकल्प: माधुरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीरवार को शुरु किए गए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेस्डर सिने तारिका माधुरी दीक्षित भी पानीपत पहुंची। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि बेटी बचाने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। तभी इस मुहिम का सार्थक परिणाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि बेटियां बेटों से कहीं आगे रहती हैं। उन्होंने अपने ही परिवार का उदाहरण दिया कि वे तीन बहनें व एक भाई हैं। लेकिन बावजूद इसके उन्हें कभी मां-बाप ने ये फर्क महसूस नहीं होने दिया कि वे लड़की हैं।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की ब्रांड अंबेसडर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित समारोह में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। -रवि कुमार

सांसद अश्विनी चोपड़ा नहीं पहुंचे समारोह में

सांसद अश्विनी चोपड़ा समारोह में नहीं पहुंचे। यह मामला चर्चा में है कि सांसद किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। वहीं मंच पर खट्टर, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मंत्री कविता जैन व राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी को ही जगह मिल पाई।

पानीपत में हुए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में कई माताएं अपनी बेटियों के साथ पहुंचीं। -रवि कुमार

मेनका गांधी के लंबे भाषण पर हुई हूटिंग

समारोह में चयनित वक्ताओं को ही मौका दिया गया था। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद माधुरी दीक्षित बोली और फिर मेनका गांधी। इसके बाद पीएम मोदी ने संबोधन दिया। अंत में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अपने संबोधन के दौरान मेनका गांधी काफी लंबा बोल गईं। इसे लेकर लोगों ने हुटिंग शुरु कर दी और मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे। ये सुनकर मोदी मंच से मुस्कुरा दिए।

मेरी बेटी मेरी खुशी

Dainik Tribune (H) , January 23, 2015, P. 3

लड़कों के समान लड़कियों की जन्मदर हासिल करने वाले गांवों को मिलेगा यह इनाम

बेटियों को बढ़ावा देने पर एक करोड़

पानीपत | एजेंसी

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ऐलान किया कि लड़कों के बराबर लड़कियों की जन्म दर हासिल करने वाले गांवों को एक करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। मेनका ने इस अभियान को जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया के बाद चौथी बड़ी पहल बताया।

मेनका ने कहा कि देश में अभी भी 46 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं, इनमें लड़कियों की तादाद 70 फीसदी है। हरियाणा में 70 ऐसे गांव हैं जहां वर्षों से एक भी लड़की नहीं जन्मी। यह लड़कियों के अस्तित्व की लड़ाई है, जिसमें उन्हें हर हाल में जीत पानी होगी।

मोदी ने किया प्रिंस का जिक्र : वर्ष 2006 में बोरवेल में गिर गए प्रिंस को बचाने के 50 घंटे चले अभियान को याद करते हुए मोदी ने कहा कि पूरे देश ने उसकी जान बचने की दिन रात प्रार्थना की थी। उन्होंने सवाल किया लोग अपने इर्द-गिर्द बच्चियों के मारे जाने को लेकर इतने संवेदनहीन कैसे हो जाते हैं। मोदी ने चेताया कि अगर हम आज से भी कन्या भ्रूण हत्या का पाप रोक कर इस अनुपात को पाटने का प्रयास करें तो भी इसे ठीक करने में 100 साल लग जाएंगे। मोदी ने कहा, 'देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षु की तरह बेटियों को बचाने की भीख मांग रहा है।' उनके लिए यह बहुत पीड़ादायक है कि एक ऐसा राज्य (हरियाणा) जिसने अंतरिक्ष की सैर करने वाली कल्पना चावला जैसी महिला को जन्म दिया। वह अन्य कल्पना चावलाओं की मां के गर्भ में ही हत्या कर देता है।

कन्या कोष योजना : हरियाणा के सीएम ने राज्य में किसी लड़की के जन्म पर 21 हजार रुपये देने की योजना शुरुआत की। बेटी जब 18 साल की होगी तो यह राशि एक लाख रुपये के तौर पर उसे दी जाएगी।

पानीपत में गुरुवार को बच्ची को सुकन्या समृद्धि खाते की पास बुक देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ हैं मुख्यमंत्री एमएल खट्टर, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और माधुरी दीक्षित।

देश में रोजाना करीब दो हजार लड़कियां मार दी जाती हैं। यह हमारे लिए शर्म का विषय है। इसे हर हाल में रोकना होगा। -मेनका गांधी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

मैं खुश हूं कि मोदी सरकार के पहले साल में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई है। मुझे इस योजना से ढेरों उम्मीदें हैं। -माधुरी दीक्षित, फिल्म अभिनेत्री

लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहन

1. बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
02 हजार रुपये लड़की के जन्म पर

2. महाराष्ट्र में सुकन्या योजना
21 हजार रुपये लड़की के जन्म पर
01 लाख रुपये 18 साल की होने पर

3. उत्तराखंड में नंदा देवी कन्या योजना
05 हजार की एफडी बेटी के जन्म पर
18 साल की होने पर लड़की को मिलेगा धन

4. केंद्र की जननी सुरक्षा
- अस्पताल में प्रसव पर महिला को 1400, आशा बहू को 600 रुपये
- गर्भवती महिला को मदद से जुड़ी तमिलनाडु की अम्मा बेबी केयर किट

साइकिल ने दी कन्या शिक्षा को रफ्तार

1. बिहार में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लड़कियों शिक्षा में बड़ा सुधार
9वीं और 10वीं की लड़कियों को दो हजार रुपये साइकिल के लिए
06-08 कक्षा की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना

2. यूपी में कन्या विद्या धन योजना
20 हजार रुपये बीपीएल परिवार की लड़की को 10वीं पास करने पर
दिल्ली में लाडली शिक्षा योजना के तहत
8वीं के बाद हर साल मदद
यूपी में दसवीं पास लड़कियों को साइकिल बांटने की योजना लागू

3. दूसरे राज्यों में प्रोत्साहन
झारखंड में लड़कियों के अलावा निर्बल आय वर्ग को भी मुफ्त साइकिल
छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना
10वीं पास लड़कियों के लिए
7.63 लाख लड़कियों को दस साल में दी साइकिल छत्तीसगढ़ में

Hindustan (H), January 23, 2015, P. 9

लगातार कम हो रही लड़कियों की संख्या

देश में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या लगातार घट रही है। इसकी वजह उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाना भी है।

पूरे भारत में (लड़कियां/1000 लड़कों के अनुपात में)

2011	2001
919	927

राज्य	2011	2001
उत्तरप्रदेश	902	916
पंजाब	846	798
दिल्ली	871	868
झारखंड	948	965
बिहार	935	942
उत्तराखंड	890	908
हिमाचल	909	896
हरियाणा	834	819
चंडीगढ़	880	845

2000 लड़कियां मारी जाती हैं रोजाना	**59.0** फीसदी कई प्रकार की अक्षमता से पीड़ित
46.0 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार	**1.40** करोड़ को प्राथमिक शिक्षा नसीब नहीं
70.0 फीसदी इनमें लड़कियां कुपोषित	**18.0** फीसदी लड़कियां प्राथमिक शिक्षा से दूर
29.0 लाख बच्चे शारीरिक अक्षमता के शिकार	**14.0** फीसदी लड़कों को नहीं प्राइमरी शिक्षा
9.90 लाख (06-14 वर्ष) इनमें से स्कूल से बाहर	**5.88** करोड़ लड़कियां प्राथमिक शिक्षा स्तर के

- पूर्वोत्तर राज्यों में लड़कियों की संख्या तेजी से कम हुई
- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम में स्थिति सुधरी
- बिहार, झारखंड, यूपी आदि में लड़कियों की संख्या तेजी से कम हुई

बदतर जिले

774/1000 : अजमेर
778/1000 : महेंद्रगढ़

बेहतर जिले

1084/1000 : केरल
1013/1000 : लाहुल-स्पीति
(0 से छह साल की उम्र के बच्चों का अनुपात)

महिला की साक्षरता भी कम

देश	74.4 %
पुरुष	82.14 %
महिला	65.46 %
बिहार	63.82 %
पुरुष	73.39 %
महिला	53.33 %
झारखंड	67.63 %
पुरुष	78.45 %
महिला	56.21 %
उत्तर प्रदेश	69.72 %
पुरुष	79.24 %
महिला	59.26 %
दिल्ली	86.34 %
पुरुष	91.03 %
महिला	80.93 %
उत्तराखंड	79.63 %
पुरुष	88.33 %
महिला	70.70 %

Hindustan (H), January 23, 2015, P. 9

'आशा' के कंधों पर 'लाडो' को बचाने की जिम्मेदारी

चंडीगढ़, 27 जनवरी (ट्रिब्यू)

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 'आशा' वर्करों और एएनएम की जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रदेश में 'लाडो' को बचाने का जिम्मा अब इनके कंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद राज्य सरकार ने आशा वर्करों एवं एएनएम की जवाबदेही तय की है। गांवों में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इन दोनों महिला कर्मचारियों की ड्यूटी तय की गई है। यही नहीं, सरकार ने उन गांवों की भी सूची तैयार करनी शुरू कर दी है, जहां प्रति एक हजार लड़कों पर बेटियों की संख्या 800 से कम है।

बताते हैं कि इस तरह के गांवों की जिलावार सूची तैयार होगी। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) से ऐसे गांवों की सूची मांगी गई है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने आज सभी जिलों के सीएमओ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि निर्देश दिए कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना पर उचित कदम उठाते हुए ऐसे गांवों की सूची तैयार करें जहां लिंगानुपात 800 से कम है।

Dainik Tribune (H) , January 28, 2015, P. 3

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

श्रीमती किरण चोपड़ा

f /kiranchopra01
kiranchopradesk@gmail.com

मोदी जी की एक और अच्छी सोच, एक अच्छा अभियान (मूवमेंट) जिसकी देश में बहुत जरूरत है, क्योंकि कितने दुःख की बात है कि जिस देश में बेटी को देवी मानकर पूजा जाता है उसे बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। आजादी के बाद लगभग 5 करोड़ कन्या भ्रूण हत्याएं हो चुकी हैं। देश के कई राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लड़कियों की संख्या कम है।

हमारा पंजाब केसरी परिवार तहे दिल से इस अभियान के साथ है और इसे सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसी के तहत मुझे एस.डी. कालेज की मैनेजमेंट और प्रिंसीपल अनुपम अरोड़ा ने 5,000 युवाओं की 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' रैली को सम्बोधित और फ्लैग करने के लिए बुलाया।

कालेज, स्कूल की मैनेजमेंट और प्रोफेसर से मिलकर और उन सबका उत्साह देखकर बहुत ही उम्मीद जागी कि इस अभियान को सफल बनाने में सबका साथ मिलेगा क्योंकि मोदी जी की अच्छी सोच, अच्छा अभियान तभी सफल हो सकता है जब सारे सामाजिक, शिक्षा संस्थान साथ जुड़ें और पूरे जोश से काम करें, गांवों के लोग साथ जुड़ें। मेरे साथ पानीपत और पानीपत ग्रामीण के एमएलए रोहिता रेवड़ी और महिपाल ढांडा भी थे। रोहिता बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की महिला हैं और महिपाल ढांडा बहुत ही सरल, स्पष्ट, जोशीले नौजवान हैं जिनके चेहरे पर उनका काम बोलता है और वह लोगों के बहुत प्रिय एमएलए हैं। इन दोनों ने ही मुझे आश्वासन दिया कि हम सब मिलकर मोदी जी के अभियान को सफल बनाएंगे।

एस.डी. कालेज की लड़कियों और लड़कों को देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि उनके चेहरे अभी भी मेरे सामने हैं और सब युवाओं के साथ मैं वट्स एप पर जुड़ंगी, उनको मैंने कोई स्पीच नहीं दी, बल्कि उनको अपने विचारों का हिस्सा बनाया और उन्होंने हर प्रश्न, हर सोच का उत्तर देकर सहमति प्रकट कर न केवल अपनी योग्यता साझा की साथ में अपने इंस्टीच्यूट का नाम भी रोशन किया कि वह कितने अच्छे संस्थान के छात्र हैं। उनके प्रोफेसर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट उनके प्रति कितने मेहनती हैं।

वाकई कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ गरीब और अशिक्षित लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। अमीर और पढ़े-लिखे लोग भी इस अपराध में बराबरी के भागीदार हैं। कितनी विचित्र बात है कि कन्या भ्रूण हत्या कर माता-पिता अत्यंत निर्दयता से अपने ही अंश की जान ले लेते हैं, जो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है।

जीवन लेने का हक तो केवल उसी को है जो जीवन देता है। फिर हम किस अधिकार से जन्म लेने से पहले ही कन्याओं को मार देते हैं? वह भी बिना किसी शर्म के, बिना किसी अपराध बोध के।

बेटी बचाओ अभियान में सबसे बड़ी बाधा हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और मानसिकता है। कन्या भ्रूण हत्या का अहम कारण हैं, एक डर कि बेटा नहीं हुआ तो वंश कैसे चलेगा? हमारा नाम कौन रोशन करेगा? हम यह बात क्यों नहीं समझते कि हमारा नाम हमारे बच्चे रोशन नहीं करेंगे। हममें खुद इतना दम तो होना चाहिए कि हम स्वयं अपना नाम रोशन कर सकें। सचिन ने क्रिकेट में, लता मंगेशकर जी ने संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन किया, शायद कई प्रतिशत लोगों को उनके माता-पिता का नाम भी नहीं पता होगा।

दूसरी सामाजिक सोच और मानसिकता कि यदि बेटी हुई तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? जरा सोचिये, इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा आपके पास रहेगा। यदि बेटा लायक निकला तो आगे बढ़ने के लिए व्यस्त रहेगा, बाहर जा सकता है और नालायक निकला तो...! क्या सभी बेटे अपने माता-पिता को बुढ़ापे में सहारा देते हैं? यदि ऐसा है तो फिर वृद्ध आश्रमों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है या अमीर-गरीब लोग बुढ़ापे में क्यों भटकते हैं। अगर यकीन न हो तो किसी मंगलवार को आप मेरे आफिस में आकर बुजुर्गों का हाल देखो।

तीसरी सोच है कि मुखाग्नि कौन देगा? आज हमारी धार्मिक मान्यता ऐसी है कि जिस बेटे ने जीते जी एक गिलास पानी के लिए न पूछा हो, लेकिन मरने के बाद मुखाग्नि वही नालायक बेटा देगा। क्या बेटियों के अग्नि देने से हमारा शरीर जलेगा नहीं? वैसे भी— *आप मरे जग परलो होई।*

चौथी सोच या यूं कह लो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो बेटी की भ्रूण हत्या का कारण बनती हैं, जिसके लिए सबको एक होकर काम करने की जरूरत है। दहेज, बच्चियों के साथ रेप या उनका शोषण। यह असल में अहम मुद्दा है, जिस पर काम करना ही होगा।

लोगों को, समाज को अपनी सोच और मानसिकता बदलनी होगी। बिना दहेज के शादियां होनी चाहिएं। जिस दिन दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी उस दिन कोख में बेटियां मुस्कराएंगी, बेटियों का अभिनंदन होगा और लोग मन्नतें मांगेंगे कि उनके यहां बेटियां हों क्योंकि—

"दोनों आंखें एक समान, बेटों जैसे बेटी महान,
करनी है जीवन की रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा,
बेटी को मरवाओगे, तो बहू कहां से लाओगे।"

Punjab Kesari (H), January 25, 2015, P. 4

Haryana to create special fund for girls: Khattar

PANIPAT: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar on Tuesday said that special fund would be created at the district level for schemes and programmes for girls' welfare right from their childhood to education.

The schemes would aim at ensuring their education, marriage, construction of separate toilets and to eradicate malnutrition, Mr. Khattar said here addressing the inaugural session of two-day National Thematic Workshop on "Best Practices for Women and Child Development." It has been organised as a part of *'Beti Bachao Beti Padhao'* programme.

Expressing concern over the gender imbalance, Mr. Khattar said that this problem is a country-wide issue. PTI

The Hindu, January 21, 2015, P. 13

(*Fund-Special fund for Girls*)

कन्या सुरक्षा पर महिला अखाड़ा की पहल

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद | निज संवाददाता

देश में कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए साधु-सन्यासियों ने लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इसकी पहल महिला अखाड़ा की ओर से की गई है। परी अखाड़ा की ओर से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान की रुपरेखा सोमवार को संगम के किनारे तैयार की गई। अखाड़ा की शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने मकर संक्रांति पर अपने शिविर में कन्या रक्षा संघर्ष समिति का गठन किया।

गोरखपुर की रहने वाली समाजसेविका प्रमिला श्रीवास्तव को समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

25 सदस्यीय समिति में अखाड़ा की महिलाओं को शामिल किया गया है। अखाड़े की योजना है कि एक साल के भीतर पूरे देश में जिला स्तर पर समिति का गठन कर लिया जाए। इस दौरान समिति की महिला सदस्य अपने क्षेत्रों में जाकर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगी।

बदलाव जारी

- साधु-सन्यासियों ने लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया
- अभियान की रुपरेखा सोमवार को संगम के किनारे तैयार की गई
- 25 सदस्यीय समिति में अखाड़ा की महिलाओं को शामिल किया गया
- कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगी

हरियाणा में 'सुकन्या समृद्धि खाता'

चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी को पानीपत से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के साथ-साथ 'सुकन्या समृद्धि खाता' नामक योजना की भी शुरुआत करेंगे। यह योजना असंतुलित लिंगानुपात और भेदभाव को दूर करने के लिए लड़कियों के प्रति सकारात्मकता लाना है। केन्द्र सरकार की 'सुकन्या समृद्धि खाता' नामक योजना के तहत लड़की पैदा होने पर खाता खुलवाया जा सकता है और यह दस साल की उम्र तक चलेगा। अधिसूचना जारी होने से एक वर्ष पहले तक जितनी भी कन्याएं 10 साल की हो चुकी हैं, वे भी इस योजना की पात्र होंगी।

Hindustan (H), January 20, 2015, P. 8

100 जिलों के हर गांव में जाएंगे प्रचार रथ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- मोदी 22 को कम लिंगानुपात वाले जिलों के लिए 72 रथ रवाना करेंगे
- हरियाणा के 12 जिलों में बेटियों को बचाने और पढ़ाने का संदेश देंगे 12 रथ
- डेढ़ घंटे की फिल्म दिखाई जाएगी, दिल्ली की कंपनी को दी जिम्मेदारी

जितेंद्र बुरा | पानीपत

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का संदेश हर गांव-शहर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार विशेष रथ रवाना करेगी। 22 जनवरी को पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे 72 रथ रवाना करेंगे। अभियान के पहले चरण में यह रथ देश के उन 100 जिलों के हर गांव में जाएंगे जहां बेटों के अनुपात में बेटियों की संख्या सबसे कम है। बिगड़ते लिंगानुपात के मामले में देश में सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुके हरियाणा के 12 जिलों में 12 रथ बेटियों को बचाने का संदेश देंगे।

इन प्रचार रथों की जिम्मेदारी सरकार ने दिल्ली की एक फर्म को दी है। हर रथ में बड़ी एलसीडी स्क्रीन होगी जिस पर बेटियों की सुरक्षा और उन्हें पढ़ाने का महत्व बताने वाली डेढ़ घंटे की फिल्म दिखाई जाएगी। सभी रथों के रूट तय किए जा चुके हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिलकर देशभर में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएंगे।

पहले चरण में 100 जिलों में डीसी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में चलने वाले इस अभियान में आम आदमी की भागीदारी तय की जाएगी। इस दौरान बेटियों पर गर्व करने और उन्हें पराया धन समझने की मानसिकता खत्म करने पर जोर रहेगा। बाल विवाह, दहेज प्रथा का विरोध करने, हर बच्ची का स्कूल में दाखिला करवाने, उनके लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

ये उठाए जाएंगे कदम

- **कानूनों का क्रियान्वयन :** गर्भ धारण पूर्व, प्रसव पूर्व निदान तकनीक, बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी कानून पर अमल।
- **स्वास्थ्य संबंधी पहल :** गर्भधारण के शुरुआती दौर में पंजीकरण, संस्थागत प्रसव और जन्म के पंजीकरण को बढ़ावा, स्वास्थ्य सेवा व पोषण।
- **शिक्षा को बढ़ावा :** लड़कियों के लिए अनुकूल वातावरण और स्कूलों में शौचालय बनवाए जाएंगे।
- **प्रशिक्षण और संवेदीकरण :** आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, एएनएम, पंचायत कार्यकर्ताओं, मेडिकल समुदाय व अन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर फील्ड में उतारा जाएगा।

जागरूकता और जुड़ाव ऐसे

- मीडिया के जरिये प्रचार। सार्वजनिक स्थलों पर गुड्डी-गुड्डा बोर्ड का प्रदर्शन।
- नुक्कड़ नाटक, प्रचार यात्राएं, रैली, प्रदर्शनी, शपथ ग्रहण समारोह और प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।
- बड़े-बूढ़ों और मता-पिता के लिए परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।
- बेटी के जन्म पर उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जेंडर चैंपियन की पहचान। समुदाय आधारित निगरानी समूह की पहचान की जाएगी।
- भागीदारी मंचों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति, ग्राम सभा और महिला सभा को जोड़ा जाएगा।

पुरस्कार दिए जाएंगे

पंचायतों, गांवों, जमीनी कार्यकर्ताओं, माताओं को अच्छा काम करने पर सम्मान और बढ़ावा।

पानीपत रिफाइनरी में सोमवार से 'बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट' विषय पर दो दिवसीय नेशनल वर्कशॉप शुरू हुई। इसमें केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कोल का विमोचन किया।

Dainik Bhaskar, January 21, 2015, P.2/Panipat Haryana

पानीपत की बेटियों ने सरकार से पूछा-हमारा स्कूल तो बंद कर दिया, अब पढ़े कैसे...

केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ समूची प्रदेश सरकार बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने पर मंथन के लिए पानीपत में जुटी हुई है जबकि उसी पानीपत शहर में सोमवार को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) के प्लांट के गेट के सामने दर्जनों बच्चियां अपना स्कूल बंद करने का विरोध कर रही थीं। 4 जुलाई 2014 को एनएफएल स्थित केंद्रीय विद्यालय को बंद कर दिया दिया था। इसमें पहली से 12वीं कक्षा तक 750 बच्चे पढ़ते थे। अब ये बेटियां सरकार से पूछ रही हैं कि उनका स्कूल तो बंद करवा दिया गया, अब वह पढ़ें कैसे।

भ्रूण हत्या के खिलाफ पानीपत से शुरू करेंगे चौथी लड़ाई : जैन

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा कि पानीपत तीन लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत यहां से कर रहे हैं। भ्रूण हत्या के खिलाफ यह चौथी लड़ाई की शुरुआत होगी।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए झज्जर के अफसर सम्मानित

झज्जर में लिंगानुपात में बेहतरीन सुधार के लिए वहां के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश धनखड़, उप जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह, औषध निरीक्षक मनमोहन तनेजा व राकेश दहिया को वर्कशॉप में सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाद झज्जर जिले का लिंगानुपात दिसंबर 2014 में 902 तक पहुंच गया। एक साल पहले तक यह 754 था।

पानीपत के सेक्टर 13-17 के मैदान में पीएम मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में पहुंचने वाले के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया है। मंगलवार को वायु सेना के हेलिकॉप्टर ने शहर का दौरा कर रिहर्सल की गई। 21 व 22 जनवरी को ऑटो की हाइवे पर एंट्री बंद कर दी गई है। रैली स्थल व पार्किंग स्थल के पास 24 पुलिस नाके लगाकर चेकिंग की जाएगी।

Dainik Bhaskar, January 21, 2015, P.2/Panipat Haryana

Conclude all femicide trials in 4 mths: SC to Haryana

New Delhi: The Supreme Court on Tuesday directed Haryana government to complete trial of cases lodged for offences of sex determination and female foeticide within four months, observing that decline in the sex ratio was "disturbing".

"Decline in sex ratio is a disturbing problem and the same is likely to affect the civilisation in entirety. Women are the basic pillar of human race in any society.

"The counsel for Haryana has submitted that sex ratio has been decreasing and the same is demonstrated in the affidavit. Declining sex ratio is a disturbing problem," a bench of justices Dipak Misra and Abhay Manohar Sapre said.

The bench, which took up the case of Haryana, said the trial in nearly 102 cases, registered under the Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act for the offences of sex determination and female foeticide, be completed within four months starting February 1.

"Trial pending before different courts, besides the cases in which the Punjab and Haryana high court or the SC have not stayed the trial, shall proceed speedily and be finalized within a period of four months commencing February 1," the bench said.

The counsel for Haryana shall provide the list of pending cases to the Registrar General of the High Court. PTI

Times of India, January 21, 2015, P.1/Panipat Haryana

BETI BACHAO, BETI PADHAO CAMPAIGN

Innovative ideas needed to prevent female foeticide, says Maneka

STARTEGY Announces a cash reward of ₹1 crore for a district which attains balanced sex ratio

Vishal Joshi
vishal.joshi@hindustantimes.com

PANIPAT: Union minister for women and child development Maneka Gandhi on Tuesday invited various stakeholders of the society to come up with innovative ideas to improve the skewed child sex ratio in the country.

Gandhi was inaugurating the two-day national thematic workshop on 'best practices for women and child development' at the Indian oil corporation refinery auditorium here. The Union minister said there are 2,000 cases of female foeticide and infanticide in the country each day "owing to the biased mindset among families".

She further said the child sex ratio was poorer in the western parts of the country and called for active participation of people to ensure women a respectable place in the society. "Official data indicates that the economic independence has a direct fall out on the skewed sex ratio. Those living under strained financial or social conditions including, the tribals, have a balanced gender ratio while there is a discouraging trend among the educated and affluent families," the minister said.

She said a hundred districts with unequal gender statistics had been identified and her ministry had set a target of nine months for them to get visible changes by various welfare and awareness programmes initiated in this direction. She said any district which manages to balance the ratio will be rewarded with ₹1 crore.

Gandhi said the deputy commissioners, gram panchayats and social organisations would be rewarded suitably for giving "workable innovative ideas" to handle the situation. "Various district administrations and social organisations have already suggested 89 ways to improve the status of women which would be evaluated by the central agencies," she said. Lauding the initiative of the district head of Gwalior for developing software which alerts the administration when any woman comes for pregnancy test, the minister announced to implement the scheme in all the identified districts. "This mechanism could be effective to maintain a watch on the women till they deliver safely. Before conducting such test, the DM offices gets a beep through the software and it could be effective in checking female foeticide," she said, adding that female infants and girls up to the age of 2-years still die due to malnutrition.

(From left) Gujarat chief minister Anandiben Patel, Union minister for women and child development Maneka Gandhi and Haryana chief minister Manohar Lal Khattar releasing the scroll 'Beti Hai to Kal Hai' during the workshop on Tuesday. PTI PHOT

WORKING ON WOMEN'S WELFARE PLANS: KHATTAR

PANIPAT: Haryana chief minister Manohar Lal Khattar on Tuesday said the state government was planning to announce a series of schemes on Women's Day on March 8.

During his speech at the national thematic workshop on 'best practices for women and child development', Khattar said his 85-day-old government was studying models of women's welfare, adding that officials were preparing a layout. It would be ready soon and announced in March, he said.

Khattar said the poor child sex ratio was a serious issue and the state government was sensitive to it.

He said there was a move to expand welfare provisions of the Ladli scheme.

"Our government is also committed to fighting malnutrition and child marriage to ensure women's empowerment in the true sense," the CM added.

Lauding the role of the district and health authorities in improving the sex ratio in Jhajjar district, Khattar said the committed officials had motivated others.

> OFFICIAL DATA INDICATES THAT THE ECONOMIC INDEPENDENCE HAS A DIRECT FALLOUT ON THE SKEWED SEX RATIO.
> MANEKA GANDHI, Union minister for women and child development

MANEKA SHARES A PERSONAL STORY

Union minister Maneka Gandhi narrated her personal experience about how her grandmother got upset when her (Maneka's) sister was born.

"Due to the family pressure, my mother paid obeisance at various religious places praying for a son. Though it happened later, my sister and I managed to do better in our respective fields," she said.

The minister highlighted the role of a particular social organisation in Haryana that was particularly working to motivate grandmothers to ensure that there was no foeticide.

Hindustan Times, January 21, 2015, P.2/Panipat Haryana

Hindustan Times, January 21, 2015, P.9/Panipat Haryana

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

राष्ट्रीय कार्यक्रम का

माननीय प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी

हुडा ग्राऊंड, पानीपत (हरियाणा)

से

22 जनवरी, 2015 (दोपहर 1.00 बजे)

शुभारम्भ करेंगे

बेटी बचाओ

बेटी पढ़ाओ

कार्यक्रम का उद्देश्य

लिंग आधारित भेदभाव का उन्मूलन करना।
बालिका का अस्तित्व व सुरक्षा सुनिश्चित करना।
बालिका की शिक्षा सुनिश्चित करना।
बालिका के पोषाहार स्तर में सुधार लाना।
बालिकाओं के लिए सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देना।
इस अभियान के मुख्य केन्द्र हरियाणा के सभी ज़िले विशेषकर गिरते लिंगानुपात जैसी गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे 12 ज़िले नामतः पानीपत, महेन्द्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, कैथल एवं भिवानी होंगे।

बेटी-बेटा एक समान - दोनों से है घर की शान

Dainik Bhaskar, January 21, 2015, P.9/Panipat Haryana

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P.13/Panipat Haryana

मुद्दा | प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर नहीं सुधारा गया तो हमारे पास अयोग्य और बेरोजगार युवाओं की फौज होगी।

बच्चों को साक्षर नहीं, शिक्षित बनाएं

चेतन भगत
अंग्रेजी के युवा उपन्यासकार

हममें से कई जब टीवी चैनलों द्वारा रात को डिनर के साथ परोसी जा रही गरमागरम राजनीति का लुत्फ उठाने में व्यस्त हैं, उसी दौरान दो हफ्ते पहले एक अहम रिपोर्ट जारी हुई है। इसे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट या एसर 2014 कहते हैं। यह ऐसा 10वां सर्वे है।

इस सर्वे को एनजीओ 'प्रथम' की मदद से जिलास्तरीय संगठन अंजाम देते हैं। एसर ग्रामीण भारत में बच्चों का सर्वाधिक व्यापक सर्वे है। एसर 2014 में 16,497 गांवों के करीब 5.70 लाख बच्चों को लिया गया।

एसर ने जानने की कोशिश की कि क्या ग्रामीण बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या वे लिखा हुआ पढ़ पाते हैं और क्या वे जोड़-घटाव कर लेते हैं? सर्वे में 15 हजार सरकारी स्कूलों को दी गई भेंट पर आधारित जमीनी रिपोर्ट भी होती है। पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। स्कूलों में नामांकनों का स्तर 96 फीसदी है अर्थात ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। बेशक, वहां क्या होता है, यह बिल्कुल अलग कहानी है। बुरी खबर बाद में। दोपहर के भोजन की योजना (85 फीसदी से ज्यादा स्कूलों में) और आधारभूत ढांचे में सुधार। करीब 75 फीसदी ग्रामीण स्कूलों में पीने का पानी व 65 फीसदी स्कूलों में टॉयलेट हैं। यह पांच साल पहले की तुलना में अहम सुधार है।

हालांकि, स्कूलों में पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। इसका मतलब है कि स्कूल उस मामले में क्या कर रहा है, जिसके लिए उसका वजूद है। विस्तृत नतीजे ऑनलाइन पर उपलब्ध हैं, लेकिन यहां आंखें खोलने वाले तीन तथ्य :

पांचवीं कक्षा के आधे बच्चे सरल हिंदी (या कोई प्रादेशिक भाषा) के वाक्य नहीं पढ़ सकते। ऐसे वाक्य, जो दूसरी कक्षा में सिखाए जाते हैं।

कक्षा पांचवीं के आधे बच्चे दो अंकों वाला घटाव नहीं कर सकते, जो दूसरी कक्षा में सिखाया जाता है।

कक्षा आठवीं के आधे बच्चे साधारण से भाग नहीं कर सकते, जो पांचवीं कक्षा में सिखाए जाते हैं।

यह हाल है हमारी शिक्षा का। स्कूल में छह साल बिताने के बाद हमारे स्कूली छात्र सामान्य वाक्य नहीं पढ़ सकते या साधारण जोड़-घटाव नहीं कर सकते। यही बच्चे यदि अच्छे निजी शहरी स्कूल में होते तो ये सारी बातें दो-तीन साल में सीख जाते। बेशक, यदि आप पढ़ नहीं सकते या छोटे-मोटे सवाल हल नहीं कर सकते तो आगे की कक्षाओं की सारी किताबें आपके सिर के ऊपर से ही जाएंगी।

हम अपने ग्रामीण स्कूलों में कर क्या रहे हैं और किस प्रकार की प्रतिभा हम पैदा कर रहे हैं? क्या हम केवल स्कूलों में भर्ती और मध्यान्ह भोजन के आंकड़ों का ही जश्न मनाते रहेंगे और स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता को भूल जाएंगे? क्या सिर्फ खुद का नाम लिख लेना या न्यूनतम स्तर पर पढ़ने और गणित के सामान्य सवालों को हल करने की योग्यता?

पढ़ने और गणित की आधारभूत योग्यता इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि बाद के वर्षों में कोई इसे नहीं सिखाता। ऐसी योग्यता से रहित छात्र को शिक्षा के कई वर्षों से गुजारना समय की बर्बादी ही होगी। आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि यदि आधारभूत कौशल शुरुआत में ही अच्छी तरह सीख नहीं लिया गया तो बाद में उन्हें सीखा नहीं जा सकता और न उसके आगे की कोई चीज। ये फिसड्डी छात्र होंगे। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में मंडराते रहेंगे और भर्ती के आंकड़ों में इनकी गिनती होगी, लेकिन अंततः अशिक्षित ही रहेंगे। यदि ऐसे बच्चे बहुत कम संख्या में होते तो हम काम चला लेते। हालांकि, हकीकत बताती है कि आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी है।

यह बदला जा सकता है। यह ऐसी समस्या है, जिसका समाधान किया जा सकता है। बशर्ते हम पहले इसकी गंभीरता समझे और फिर हमारी सरकार में इसे प्राथमिकता दी जाए। खेद की बात है कि हमारी कथित बौद्धिक बहसें राजनीतिक और व्यक्तित्व आधारित प्रतियोगिताएं हो गई हैं। चूंकि इस समस्या के साथ कोई जाना-पहचाना चेहरा जुड़ा हुआ नहीं है, हम इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते और इसीलिए मीडिया भी इसकी उपेक्षा करता है, जबकि यह अहम मुद्दा है।

हालांकि, इन लाखों बच्चों और उनके परिवारों के साथ यह धोखेबाजी होगी। साफ कहूं तो हम पढ़े-लिखे लोग हमारे ग्रामीण बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इसकी जरा भी परवाह नहीं करते। वे हमारे नहीं हैं और स्पष्टता से कहें तो वे हमारे जैसे लोगों से बहुत अलग हैं। हालांकि, यदि हम समस्या का सामाधान नहीं करते तो अगले एक या दो दशकों में हमारे सामने लाखों भूखे और रोजगार मांगने वाले ऐसे युवा होंगे, जिनके पास न तो कोई योग्यता होगी और न दुनिया के बारे में शिक्षित होने से आया कोई नजरिया होगा। यदि हम नहीं चाहते कि साधारणता का यह टाइम बम हमारे ऊपर फटे, तो आइए, हम ग्रामीण शिक्षा को सुधारने पर काम करें। काम में लाए जा सकने वाले कुछ आइडिया ऐसे हैं :

टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें : अच्छे शिक्षकों की कमी है, लेकिन यदि हम किसी क्षेत्र में कुछ स्कूलों को एकजुट करें और वर्चुअल क्लास (जिन्हें वरिष्ठ शिक्षक चलाएं) तथा वास्तविक कक्षाओं (जिन्हें कम कुशल शिक्षक अंजाम दें) का मिला-जुला इस्तेमाल करें तो कार्यकुशलता हासिल करने की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। नेशनल क्लासरूम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शुरुआती शिक्षा में व्यक्तिगत मार्गदर्शन की जरूरत होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर स्थानीय स्तर पर स्कूलों का क्लस्टर बनाना उपयोगी होगा।

रिपोर्टिंग सिस्टम : स्कूल खोलकर उसमें छात्रों को भरती करना काफी नहीं है। किसी भी सेवा प्रदाता की तरह, इसे भी दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाना होगा। इमारत में बच्चों की गिनती करने की बजाय बच्चों के कौशल पर निगरानी तरक्की का दूरगामी फायदा होगा। इसके लिए कोई केंद्रीकृत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

कक्षा और ग्रेड आधारित व्यवस्था को बदलिए। संभव है कि शुरुआती वर्षों में कक्षा 1 से 12वीं वाली व्यवस्था काम न दें। जब तक किसी छात्र या छात्रा में आधारभूत योग्यता नहीं आती, उसे ऊंची कक्षा में भेजा नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चों पर कोई भी एग्जाम व टेस्ट का दबाव नहीं डालना चाहता। हमें शुरुआती वर्षों के लिए हकीकत में कितना सीखा है, इस आधार पर हर्डल मार्कर बनाने चाहिए।

पाठ्यसामग्री में सुधार लाएं। हमारी पाठ्यसामग्री बहुत पुरानी पड़ चुकी है। नए जमाने से उसका कोई वास्ता नहीं है। रटने की जो पद्धति हम बच्चों पर लादते हैं वह न सिर्फ उसे किसी विषय को समझने से रोकती है बल्कि समझ या तर्क के किसी कौशल को हासिल किए बिना उसे शिक्षा व्यवस्था की पायदान पर आगे बढ़ाती रहती है।

ये तो कुछ थोड़े से सुझाव हैं। देश में मौजूद कई प्रखर प्रतिभाएं और भी सुझाव दे सकती हैं। समाधान तो मिल जाएगा, बशर्ते नागरिकों में, सनसनीखेज की बजाय जो महत्वपूर्ण है उसे तरजीह देने की आकांक्षा हो। हमारे आधे से ज्यादा विद्यार्थी, अर्द्ध-शिक्षित भी नहीं हैं। क्या इस पर पूरा ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं है?

chetan.bhagat@gmail.com

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P.4/Panipat Haryana

तीन लड़ाइयों का गवाह पानीपत आज लड़ेगा बेटियों की लड़ाई

- राष्ट्रीय अभियान **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- फिल्म अभिनेत्री **माधुरी दीक्षित** बनी ब्रैंड एंबेसडर, कार्यक्रम में भी रहेंगी मौजूद

भास्कर न्यूज | पानीपत

बेटियों को बचाने, उन्हें पढ़ाने की आवाज पानीपत से बुलंद होगी। दुनिया को कर्म करने का संदेश देने वाले हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रव्यापी मुहिम का शुभारंभ करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक दिशा-दशा बदलने वाली तीन लड़ाइयों का गवाह बना पानीपत अब बेटियों के लिए लड़ेगा।

नरेंद्र मोदी

माधुरी दीक्षित

मोदी का हेलिकॉप्टर दोपहर करीब 2 बजे यहां के सेक्टर 13/17 के दशहरा मैदान में उतरेगा। प्रधानमंत्री 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना' के तहत जनसभा में कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं। मशहूर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को योजना का ब्रैंड एंबेसडर बनाया गया है। पीएम के साथ वे भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। प्रदेश व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आलावा कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे।

पानीपत. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत जागरूकता रैली निकालती छात्राएं।

बेटियों के लिए ये घोषणाएं करेंगे मोदी

'प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि खाता योजना' : लड़की पैदा होने पर खास बैंक खाता। यह बच्ची के 10 वर्ष की होने तक चलेगा। अधिसूचना जारी होने से एक वर्ष पहले तक जितनी कन्याएं 10 वर्ष की हो चुकी हैं, उनका भी खाता खुल सकेगा। हजार रु. से खुलेगा खाता। वित्त वर्ष में डेढ़ लाख रु. तक जमा करा सकेंगे। इस पर आयकर छूट मिलेगी। अन्य जमा योजनाओं से ज्यादा ब्याज। सांकेतिक रूप से पानीपत जिले की 5 बेटियों का खाता खोला जा चुका है। पीएम आज उन्हें पासबुक सौंपेंगे।

- 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' पर पीएम एक डाक टिकट भी जारी करेंगे।
- 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का संदेश देने के लिए प्रचार रथ का शुभारंभ करेंगे। देश के चिन्हित जिलों में ये प्रचार रथ जागरूकता फैलाएंगे।

लाडली योजना का दायरा तीन बच्चियों तक हो सकता है : बेटियों के लिए लाडली योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। अभी पहली और दूसरी लड़की होने पर सरकार की ओर से बैंक में 5000 रुपए जमा कराए जाते हैं। अब तीसरी लड़की पैदा होने पर भी यह लागू होगा।

दो दिवसीय कार्यशाला खत्म, मेनका ने रखा सुझाव

लिंग जांच को कानूनी दर्जा मिले, मॉनिटरिंग सख्त हो

पानीपत | केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लिंग जांच को कानूनी दर्जा देकर सख्त मॉनिटरिंग की वकालत की। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या में मर्जी मां-बाप की होती है, तो क्यों न जांच कराकर निश्चित कर लिया जाए कि आने वाला बेटा है या बेटी। फिर अगर किसी ने गर्भपात कराया तो उस पर कार्रवाई करें। महाराष्ट्र की महिला-बाल कल्याण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने यह विकल्प रखा था। 'बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट' पर सेमिनार बुधवार को समाप्त हो गया।

यह करेगी सरकार

- देश के सभी 660 जिलों में विशिष्ट काम करने वाली एक-एक महिला को सम्मानित किया जाएगा। मेनका गांधी ने सभी जिलों से ऐसी महिलाओं का नाम मांगा है। इनका 8 मार्च को महिला दिवस पर सम्मान होगा।
- बेटी संबंधी योजनाओं का एनसीआरटी की सभी किताबों के कवर पेज के पीछे विज्ञापन छापा जाएगा। इसमें बेटियों से जुड़ी योजनाएं होंगी, ताकि लड़कियां खुद लाभ लेने के लिए आगे बढ़ें।

हर गांव में आंगनबाड़ी बनाने का सुझाव: केंद्रीय मंत्री ने हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र या सामुदायिक केंद्र बनाने का सुझाव रखा। ससुराल से प्रताड़ित महिला जरूरत पर उसी केंद्र में रात बिताए। वहां उसे खाना भी मिले। • पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिले। • महिलाओं से जुड़ी शिकायतें एक ही जगह दर्ज की जाएं। • महिला आयोग को और ज्यादा अधिकार दें ताकि वह अपने स्तर पर दोषियों को सजा दे सके। • लोगों को ऐसी फिल्म दिखाई जाए, ताकि उन्हें भ्रूण हत्या में होने वाली दिक्कत और अजन्मे बच्चे/बच्चियों के दर्द का अहसास हो।

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P.1/Panipat Haryana

अच्छी पहल

बेटी के जन्म पर 51 सौ रुपए की एफडी करवाएगी नैन पंचायत

मतलौडा। गांव के किसी भी घर में बेटी के जन्म पर पानीपत जिले की नैन ग्राम पंचायत उसके नाम 51 सौ रुपए की एफडी करवाएगी। यह फैसला पंचायत ने मंगलवार को सर्वसम्मति से ग्राम सभा की बैठक में लिया। पंचायत की सरपंच सरोज रानी ने इसकी घोषणा गांव की जनरल चौपाल में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाने के दौरान की। सरपंच ने बताया कि एफडी बेटी के नाम पर होगी और इसकी अवधि 20 साल होगी। 20 साल बाद बेटी खुद इस पैसे को ले पाएगी। पंचायत ने बेटियों को बचाने के लिए यह पहल की है।

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P.2/Panipat Haryana

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P.5/Panipat Haryana

वर्कशॉप के दूसरे दिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अपनी मां की कहानी सुनाई

तीन बेटियों की मां बन जाती है पटरानी : मेनका

भास्कर न्यूज |पानीपत

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार को वर्कशॉप के दूसरे दिन भी अपनी मां की एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मां कहती थी-एक बेटी होने पर मां रानी बन जाती है, दूसरी होने पर महारानी और तीसरी होने पर पटरानी।

उन्होंने कहा कि वहीं एक बेटा होने पर मां नौकरानी बन जाती है। इसलिए बेटी को बढावा दें। इसके लिए उन्होंने हर महीने चयनित 100 जिलों के डीएम से रिपोर्ट लेने की बात कही।

21 बच्चों को किया सम्मानित

15 जनवरी को प्रदेश में आयोजित पेंटिंग, स्लोगन और निबंध प्रतियोगिताओं में राज्य-स्तर पर पहले तीन स्थान हासिल करने वाले बच्चों को केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सम्मानित किया। सबसे पहले कस्तूरबा गांधी विद्यालय नूंह मेवात की छठी की छात्रा वसीमा को सम्मानित किया गया, जिसको केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। सम्मानित होने वालों में निबंध लेखन में प्रथम रहने वाली आसन कलां की पिंकी को भी सम्मानित किया गया।प्रतियोगिता में प्रदेश के 19 हजार 214 स्कूलों में 32 लाख 89 हजार बच्चों ने भाग लिया था।

बीबीपुर के सरपंच ने कहा "लड़की हुई है"

कार्यशाला का अंतिम सेशन बालिका की महत्ता विषय पर था। चर्चा के लिए सबसे पहले जींद जिले के बीबीपुर ग्राम पंचायत के सरपंच सुनील जागलान को आमंत्रित किया गया। सरपंच ने कहा कि "लड़की हुई है" के ये तीन शब्द बहुत ही मायने रखते है। दो साल पहले उन्हें जब बेटी हुई तो नर्स को बख्शीस देने लगे। इस पर नर्स ने कहा कि बेटा होता तो ले लेते, बेटी हुई है डॉक्टर नाराज होंगी। सरपंच ने कहा कि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने गांव में चलाए गए कई कार्यक्रमों का उल्लेख किया। शहीदों की तर्ज पर ग्राम पंचायत के मुख्य सड़क का नाम लाडो मार्ग रखा, महिला चबूतरों का निर्माण कराया, महिला पुस्तकालय बनवाए, खाप पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी की जो हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बात है। उनके गांव में लड़की के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है।

यूपी को बताया बीमार

मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश को बीमार प्रदेश बताते हुए कहा कि वहां पैसे के अभाव में योजनाएं बैठ जाती हैं। इसलिए पंचायत मनरेगा स्कीम का लाभ उठाए और हर गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाकर गांव को सबल बनाए ताकि महिलाओं को जगह मिल सके। हालांकि, उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 100 जिलों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P.6/Panipat Haryana

कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों को गोद लिया जाए : माया सिंह

पानीपत | बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में पोषण और स्वास्थ्य विषय पर चर्चा के दौरान मांग की गई की प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गांव को गोद लेने की योजना शुरू की है, ठीक इसी तरह से कुपोषित बच्चों को भी क्यों न गोद लिया जाए। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने यह प्रयोग किया जो बहुत सफल हुआ है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक गांव में 700 बच्चे कुपोषण के शिकार थे। वहीं उस गांव में 1000 सामर्थ्यवान थे। ऐसे में हमने सोचा क्यों न एक-एक बच्चे की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी जाए। एक सप्ताह में ही फर्क दिखने लगा। माया सिंह ने बच्चों में भूख व पोषक तत्व की कमी की ही समस्या नहीं है। पानी की वजह से भी समस्या हो सकती है।

लड़कियों को बनाएं डिसिजन मेकर : कुमार

महिला सशक्तिकरण विषय की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ललिता कुमार मंगलम ने कहा कि भारत में डिसिजन लेने वाली महिलाएं बहुत ही कम हैं। हमें निर्णय लेने वाली महिलाएं बनानी होंगी, तभी महिला सशक्तिकरण संभव हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि चीन में यह 51 प्रतिशत, रूस में 42 और भारत में 15 प्रतिशत से भी कम है। कुमार मंगलम ने कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। वहीं डॉ. पाम राजपूत ने जेंडर बजट की मांग की। राजपूत ने हर जगह महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की मांग की। साथ ही कहा कि आर्थिक रूप से महिलाओं को लीडर बनाना है।

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P.6/Panipat Haryana

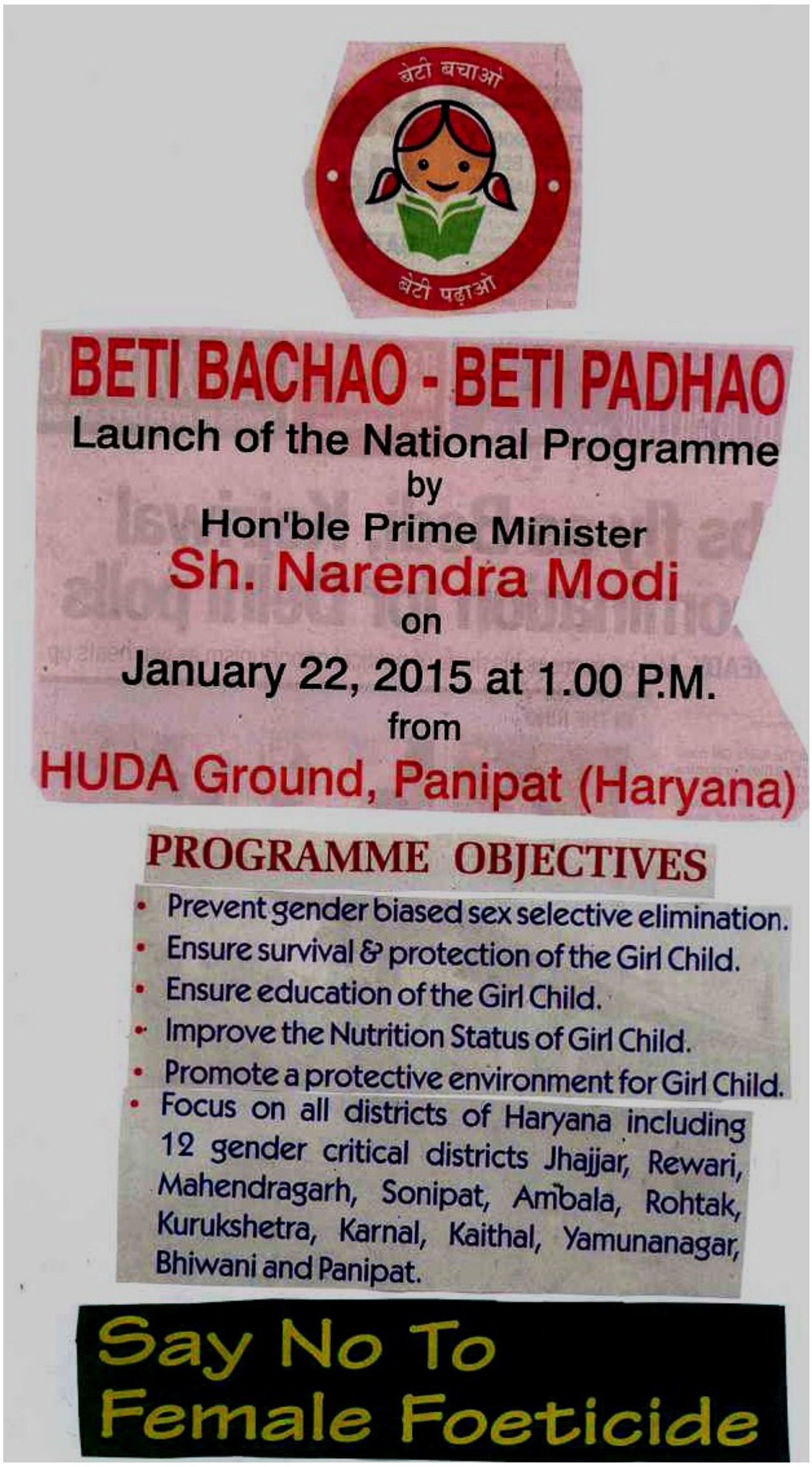

Hindustan Times, January 22, 2015, P.2/Panipat Haryana

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

देश के 100 जिले बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के पहले चरण में शामिल किए गए हैं। इन जिलों का चयन तीन कारणों से हुआ है। सबसे पहले वे जिले हैं, जहां बेटियों (0-6 साल तक) का अनुपात लड़कों की तुलना में सबसे कम है। उन जिलों को भी योजना में शामिल किया गया है, जहां का अनुपात राष्ट्रीय औसत 918 के आसपास यानी थोड़ा कम या थोड़ा अधिक है। लेकिन, अनुपात घटते-बढ़ते रहने का रुझान है। उन जिलों को भी शामिल किया गया है जहां राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर आंकड़े हैं। जैसे-सिक्किम में उत्तरी सिक्किम और जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले। उत्तरी सिक्किम में प्रति हजार बेटों पर बेटियों की संख्या 1103 और बड़गाम में 1007 (2013-14) है। इन्हें बाकी जिलों को प्रेरित करने के उद्देश्य से योजना में शामिल किया गया है।

ये सौ जिले बदले, तो बदलेगा देश

▪ हरियाणा के सर्वाधिक 12 जिले, सबसे कम औसत वाले 3 जिले करनाल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ▪ पंजाब-11, राजस्थान-10 और दिल्ली के 5 जिले

मानचित्र पर समझें हालात

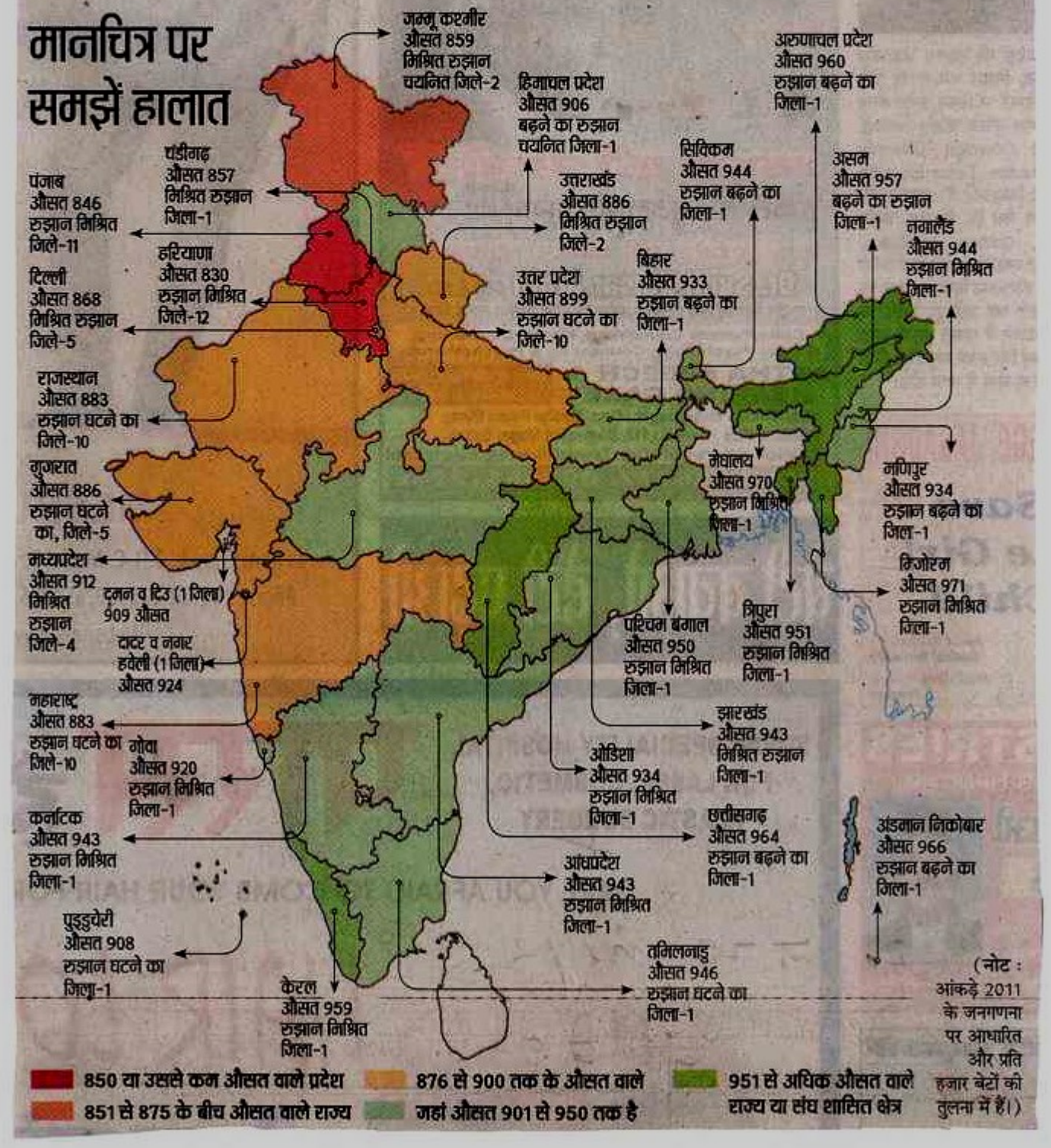

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P.12/Panipat Haryana

उत्तरी सिक्किम-बड़गाम सहित श्रेष्ठ अनुपात वाले 12 जिले

देश के कई जिले चाइल्ड सेक्स रेशो में काफी अच्छी स्थिति में हैं। इन जिलों में राष्ट्रीय औसत 919 से कहीं बेहतर हालात हैं। हालांकि, ये जिले जम्मू कश्मीर, सिक्किम, दमन व दिउ, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे कम आबादी वाले छोटे राज्यों के हैं। फिर भी ये देशभर के बाकी जिलों के लिए उम्मीद की किरण बिखेर रहे हैं। इन्हें नीचे चार्ट में देखा जा सकता है।

क्र.	जिला	राज्य	2001	2011	2013-14	2014-15	लक्ष्य 15-16
1.	उ. सिक्किम	सिक्किम	995	929	1103	मेंटेन	मेंटेन
2.	बड़गाम	जे एंड के	963	832	1007	मेंटेन	मेंटेन
3.	अनंतनाग	जे एंड के	977	841	976	मेंटेन	मेंटेन
4.	पुलवामा	जे एंड के	1046	829	963	मेंटेन	मेंटेन
5.	दमन	दमन व दिउ	907	897	961	मेंटेन	मेंटेन
6.	सेनापति	मणिपुर	962	893	957	मेंटेन	मेंटेन
7.	त्रिसूर	केरल	958	950	956	मेंटेन	मेंटेन
8.	रिभोई	मेघालय	972	953	952	मेंटेन	मेंटेन
9.	गंगानगर	राजस्थान	850	854	949	959	मेंटेन
10.	निकोबार	अंडमान निकोबार	937	945	946	956	मेंटेन
11.	सवाईमाधोपुर	राजस्थान	902	871	942	952	मेंटेन
12.	हैदराबाद	तेलंगाना	943	914	941	951	मेंटेन

इन जिलों में भी करनी होगी मशक्कत

दिल्ली में प. दिल्ली-875, उत्तर प्रदेश में आगरा-878 व गाजियाबाद-906, हरियाणा में भिवानी-879, अम्बाला-881, कैथल-903, रोहतक-909 व यमुनानगर-913, पंजाब में बरनाला-878, मानसा-885, फिरोजपुर-894, फतेहगढ़ साहिब-893 व मोहाली-910, गुजरात में गांधीनगर-885, अहमदाबाद-890 व राजकोट-891, महाराष्ट्र में जलगांव-889, कोल्हापुर-900, जम्मू कश्मीर में जम्मू-893, मध्यप्रदेश में ग्वालियर-901 व भिंड-908, हिमाचल में ऊना-902, राजस्थान में जयपुर-908, चंडीगढ़-909।

(नोट : वर्ष वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर।)

इन 25 जिलों में हालात बदतर

क्र.	जिला	राज्य	2001	2011	2013-14	2014-15	लक्ष्य 15-16
1.	करनाल	हरियाणा	809	824	736	746	756
2.	महेंद्रगढ़	हरियाणा	818	775	792	802	812
3.	रेवाड़ी	हरियाणा	811	787	805	815	825
4.	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	771	818	819	829	839
5.	झज्जर	हरियाणा	801	782	827	837	847
6.	सोनीपत	हरियाणा	788	798	832	842	852
7.	सूरत	गुजरात	859	835	845	855	865
8.	सांगली	महाराष्ट्र	851	867	845	855	865
9.	गौतमबुद्ध नगर	यूपी	854	843	847	857	867
10.	द. पश्चिम दिल्ली		846	845	848	858	868
11.	मेरठ	यूपी	857	852	850	860	870
12.	बागपत	यूपी	850	841	852	862	872
13.	कुड्डलूर	तमिलनाडु	957	896	852	862	872
14.	बुलदाना	महाराष्ट्र	908	855	852	862	872
15.	संगरूर	पंजाब	784	840	853	863	873
16.	धनबाद	झारखंड	951	916	853	863	873
17.	पटियाला	पंजाब	776	837	856	865	876
18.	झांसी	यूपी	886	866	858	868	878
19.	बुलंदशहर	यूपी	867	854	859	869	879
20.	तरणतारण	पंजाब	784	820	860	870	880
21.	नयागढ़	ओड़िशा	904	855	860	870	880
22.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	890	858	860	870	880
23.	कठुआ	जम्मू कश्मीर	847	831	862	872	882
24.	मुजफ्फरनगर	यूपी	859	863	863	873	883
25.	गुरदासपुर	पंजाब	789	821	864	874	884

बाल श्रम बच्चियों के लिए अभिशाप

भारत

2.80 करोड़ बच्चे (5-14 साल) देश में हैं बाल श्रमिक।

1.40 करोड़ यानी आधी हैं बेटियां इनमें।

दक्षिण एशिया

4.40 करोड़ बाल श्रमिक हैं दक्षिण एशियाई देशों में। इनमें बच्चियां 43%

एशिया प्रशांत

7.77 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लगे हैं एशिया प्रशांत देशों में। इनमें लड़कियां महज 30%

इन देशों में दक्षिण एशियाई देशों के साथ ही चीन, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, पूर्वी तिमोर, ताइवान, फिलिपींस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, किर्गिस्तान आदि शामिल।

घर से ही होती है शुरुआत

बेटियों के स्कूल न जा पाने और कई प्रदेशों में गर्ल चाइल्ड लेबर की ओर धकेले जाने की शुरुआत घर से ही होती है। सेव द चाइल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट-2014 के अनुसार मध्यम और उच्च मध्यम आमदनी वाले परिवारों में बेटियां अनजाने में घर के कामकाज में लग जाती हैं। वहीं, निम्न आय वाले परिवारों में पहले मां-बाप का हाथ बटाने के लिए काम करती हैं। फिर, अपने परिवार के लिए उपार्जन का आधार बन जाती हैं। इस तरह उनका अपने घरों से दूसरे प्रांतों तक पलायन हो जाता है। पंजाब और महाराष्ट्र में खेती के लिए कर्ज में डूबे परिजनों की आर्थिक मदद के लिए बेटियां काम में लग जाती हैं। वहीं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से बेटियों का रोजगार के लिए पलायन हो जाता है। वे फिर, मानव तस्करी का शिकार हो जाती हैं। इसलिए, इनसे भी बचना होगा। तभी बेटियां पढ़ पाएंगी जैसे :

1. अरे, रानी जरा गैस की नॉब बंद कर देना।
2. देखो तो, कहीं दूध उबलकर गिर न जाए।
3. आज बहुत थक गई हूं, जरा चाय बना ले तू...
4. दस साल की हो गई, दाल तो रख दे कूकर में...। फिर छोटे भाइयों की जिम्मेदारी और पापा के कपड़े धोना। इसी तरह स्कूल जाना बंद।

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P. 12/Panipat Haryana

लिंगानुपात में महिलाएं बढ़ रहीं, पर घट रहीं बेटियां

अभी केंद्र सरकार की योजना प्रति हजार बेटों की संख्या की तुलना में बेटियों की संख्या को कम से कम 950 तक ले जाना है। जिन जिलों में यह औसत पहले से ही बराबर या अधिक है, वहां अनुपात बनाए रखने के लिए काम किया जाएगा। लेकिन, देश में 1961 से 2011 तक की छह जनगणनाओं के मुताबिक कुल लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या बढ़ने या मैटेन रहने का ट्रेंड है। वहीं, छह साल तक की बच्चियां घट रही हैं। (नीचे ग्राफ पर)

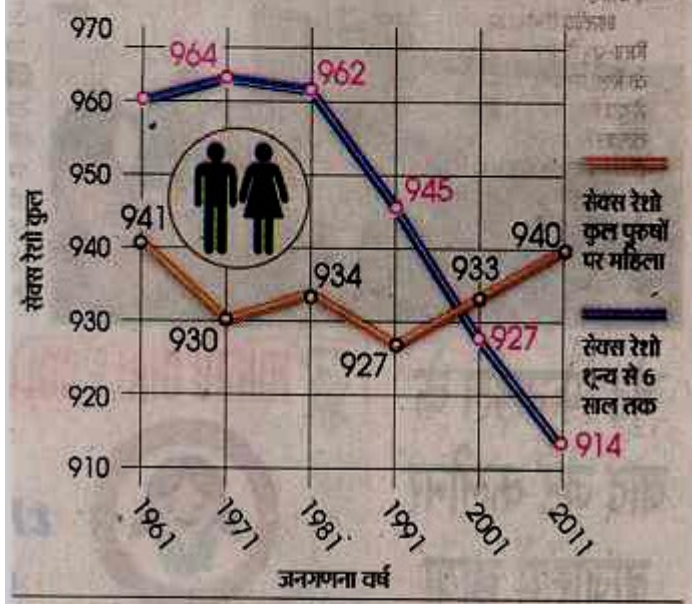

ग्लोबल जेंडर गैप

दुनिया के बाकी देशों की तुलना में हम काफी पीछे, 135 देशों के सर्वे में 105वां स्थान है हमारा

(स्रोत : ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट-2012)

अनुकूल माहौल का अभाव

बेटियों को पढ़ाने के लिए सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने की जरूरत

द वर्ल्ड ऑफ इंडियाज गर्ल्स (विंग्स) की सेव द चाइल्ड रिपोर्ट-2014 के मुताबिक देश में 18 साल से कम उम्र की बेटियों की संख्या 22.50 करोड़ है। निजी स्कूलों में एडमिशन के 2012 तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 6-14 साल तक की उम्र के कुल बच्चों में केवल 45 प्रतिशत बेटियां थीं। यानी 55 फीसदी बेटे। इस 10 प्रतिशत के अंतर को खत्म कर बराबरी पर लाने के लिए योजना में खास इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि, कक्षा बढ़ने के साथ-साथ लड़कियों के ड्रॉपआउट बढ़ने का कारण अनुकूल माहौल की कमी और असुरक्षा की भावना भी है।

70.2% लड़कियां 10वीं तक जाते-जाते पढ़ाई छोड़ चुकी होती हैं।

41.3% बेटियां 8वीं तक जाते-जाते बंद कर देती हैं स्कूल जाना।

24.4% बच्चियां 5वीं कक्षा से भी पहले ही छोड़ देती हैं पढ़ाई।

5.6% सालाना दर से बेटियां अपर प्राइमरी हो जाती हैं ड्रॉपआउट

▶ **31.6%** हो गई शिक्षिकाओं की संख्या कम होते-होते 2012 तक। यानी बढ़कर 68.4% तक पहुंच गए पुरुष शिक्षक। इनसे छात्राएं अपनी समस्याएं नहीं बता पाती हैं।

▶ **38.1%** थी देश में अपर प्राइमरी स्तर तक के स्कूलों में शिक्षिकाओं की संख्या 2001 में। यानी 61.9 फीसदी ही पुरुष शिक्षक थे।

छेड़छाड़ और प्रताड़ना के कारण छूट जाती है पढ़ाई

घर से 3-3 किमी दूर स्कूल होने व आते-जाते रास्ते में छेड़छाड़ के मामलों के कारण बेटियां स्कूल जाना ही छोड़ देती हैं। छींटाकशी और हिंसा का भी असर पड़ता है। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार शोषण के शिकार बच्चों में 45.3% लड़कियां होती हैं। जिस उम्र में लड़कियां हायर सेकेंडरी या कॉलेज में होती हैं, उसी उम्र में यौन शोषण के मामले बढ़ते हैं। 14.2% बच्चियां 15 से 19 साल की उम्र में इसकी शिकार होती हैं। 5% को 10 से 15 साल की उम्र में व एक फीसदी बच्चियों को ऐसे जघन्य अपराध का सामना 10 साल से कम की उम्र में ही करना पड़ता है।

1. **8542** केस केवल 2012 में दर्ज हुए बच्चियों के साथ रेप के

2. **11502** बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जांच हुई 2011-12 में (पुराने पेंडिंग केस के साथ)

3. **7539** मामलों में ही पुलिस चार्जर कर सकी चार्जशीट

4. **1447** मामलों में ही सालभर में तय हो सकी सजा

स्कूलों में टॉयलेट की कमी भी बड़ी बाधा

देश में 4.70 लाख प्राइमरी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं हैं। जबकि, केवल 2.68 लाख लड़कों के स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। 1 लाख प्राइमरी स्कूल में पीने का पानी नहीं है। 5 लाख स्कूलों में तो भवन ही नहीं है। बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हैं।

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P. 12/Panipat Haryana

Dainik Bhaskar, January 22, 2015, P. 12/Panipat Haryana